नई दिल्ली ■ मंगलवार 03 फरवरी 2026 ■ मूल्य 5.00 ■ वर्ष 13 ■ अंक 307 ■ पृष्ठ 08

JBT

जनभावना टाइम्स

www.thejbt.com

निष्पक्ष और निर्भीक खबर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, देहरादून, लखनऊ, अलीगढ़, मथुरा, हिसार, कैथल एवं करनाल से प्रकाशित

04 सहजन के फूलों में नवजीवन का उल्लास | 07 खेलमंत्री मांडविया ने 'माय भारत बजट क्वेस्ट 2026' लांच किया | रणबीर कपूर की 'रामायण' पर अरुण गोविल का बड़ा बयान 08

राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा

लोकसभा दिनभर के लिए स्थगित

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सदन में एक पूर्व सेना प्रमुख के संस्मरण के मसौदे के कुछ अंश का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधने का प्रयास किया, जिस पर सत्तापक्ष और कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक एवं हंगामा देखने को मिला तथा सदन की कार्यवाही बाधित हुई।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष की बातें पूरी तरह से काल्पनिक हैं और वह सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सदन में गतिरोध बने रहने पर सभा की बैठक पहले अपराह्न दो बजकर नौ मिनट पर अपराह्न तीन बजे तक, दूसरी बार तीन बजकर आठ मिनट पर शाम चार बजे तक और फिर चार बजकर 10 मिनट पर मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष सदन में पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे की पुस्तक

'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के मसौदे के उस अंश को पढ़ना चाहते थे जिसमें 31 अगस्त, 2020 की एक घटना का उल्लेख है। यह संस्मरण अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस नेता से कई बार यह अपील की कि वह पुस्तक या किसी पत्रिका को सदन में उद्धृत नहीं कर सकते, हालांकि राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख का हवाला देते हुए चीन के साथ भारत के सैन्य तनाव का विषय उठाने का प्रयास किया और दावा किया कि पूर्व सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चरित्र के बारे में भी बताया है।

इस विषय पर कार्यवाही पहली बार स्थगित होने से पहले जब लोकसभा में गतिरोध जारी था तब प्रधानमंत्री मोदी भी सदन में मौजूद थे। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अपने भाषण की शुरुआत में ही भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए पलटवार करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि सूर्या ने कांग्रेस की देशभक्ति और चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं, इसलिए वह एक पूर्व सेना प्रमुख के उस संस्मरण के अंश को पढ़ना चाहते हैं जो एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने जैसे ही इसे पढ़ने का प्रयास किया तो राजनाथ सिंह ने सवाल उठाया कि नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कि वह जिस पुस्तक का उल्लेख कर रहे हैं, वो प्रकाशित हुई है या नहीं।

गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि सदन में पुस्तक और पत्रिका में प्रकाशित बातों को नहीं रखा जा सकता और नेता प्रतिपक्ष को व्यवस्था का पालन करना चाहिए। बिरला ने राहुल गांधी से कई बार कहा कि वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखें। जब राहुल गांधी इस संस्मरण के कुछ अंश सदन के पटल पर रखने पर अड़े रहे तो बिरला ने कहा कि आप लगातार आसन की अवमानना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वह आसन को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि चीन के साथ भारत के रिश्ते के बारे में बात रखना चाहते हैं।

सदन में लगातार गतिरोध बने रहने पर बिरला ने लोकसभा की बैठक अपराह्न दो बजकर नौ मिनट पर अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा की बैठक पुनः शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर इसी मुद्दे को रखने का प्रयास किया और कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। कांग्रेस नेता की बातों का विरोध करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ये पूरी तरह काल्पनिक बातें हैं, नेता प्रतिपक्ष सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इस विषय पर बोले जाने से रोका जाए।राहुल गांधी ने कहा कि जो हुआ है, उसके बारे में सेना के हर जवान को पता है, लेकिन सरकार इस बात को जनता से छिपाना चाहती है।

कोई व्यक्ति या संगठन कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता: चुनाव आयोग

नई दिल्ली। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया से जुड़े कई मुद्दों को उनके समक्ष उठाया। सूत्रों ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तृणमूल प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश में कानून का राज सर्वोपरि रहेगा। कोई भी व्यक्ति या संगठन यदि कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके विरुद्ध निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्तियों और कानून के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के कुछ विधायक खुले तौर पर निर्वाचन आयोग, विशेष रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ अपमानजनक, अभद्र और धमकी भरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही चुनावी कार्यों में लगे अधिकारियों को धमकाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। राज्य में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और विधायकों द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों—जिनमें उप-मंडल अधिकारी और प्रखंड विकास अधिकारी कार्यालय शामिल हैं—में तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हुई हैं।

सूत्रों के अनुसार निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया कि एसआईआर प्रक्रिया में लगे किसी भी अधिकारी पर किसी भी प्रकार का दबाव, बाधा या हस्तक्षेप पूरी तरह अस्वीकार्य है और ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाया जाएगा। इस बीच, बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को देय मानदेय को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई है।

प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी को कुल 18,000 रुपये का मानदेय मिलना है, लेकिन अब तक केवल 7,000 रुपये का ही भुगतान किया गया है। आयोग ने शेष राशि का शीघ्र और बिना किसी और देरी के भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

पुणे के कथित मुंडवा जमीन घोटाले में पार्थ पवार को राहत

मुंबई। महाराष्ट्र के पुणे जिले के बहुचर्चित मुंडवा जमीन घोटाले में सोमवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार और उनके सहयोगी दिग्विजय पाटिल को बड़ी राहत मिली है। पुणे की खडक़ क्राइम ब्रांच की ओर से आज पुणे अदालत में पेश की गई 1886 पन्नों की चार्जशीट में सिर्फ शीतल तेजवानी को आरोपित बनाया गया है। इस मामले की छानबीन कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुणे के मुंडवा जमीन घोटाले की 1886 पन्नों की चार्जशीट आज अदालत में पेश की गई है। अब तक जांच के अनुसार चार्जशीट में शीतल तेजवानी ही मुख्य आरोपित हैं। जबकि अब तक की जांच में पार्थ पवार और उनके सहयोगी का कहीं सहभाग के तथ्य नहीं मिले हैं। समाजसेविका अंजली दमानिया ने इस चार्जशीट पर सवाल खड़ा किया है। अंजली दमानिया ने कहा कि क्या महाराष्ट्र सिर्फ़ राजनीतिक दलाली का अड्डा बन गया है? क्या क़ानून सिर्फ़ आम आदमी के लिए है? क्या नेताओं के लिए 'न्याय' शब्द खत्म हो गया है? इस चार्जशीट का मतलब बड़े लोगों के लिए न्याय का कोई अर्थ शेष नहीं बचा है, जबकि गरीब लोगों को न्याय की कड़ी फटकार पड़ती है। पुणे ज़मीन घोटाले में खडक़ पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है, लेकिन वह भी सिर्फ शीतल तेजवानी के खिलाफ! तो फिर दिग्विजय पाटिल और पार्थ पवार के खिलाफ जांच का क्या?

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सोनम वांगचुक का बयान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि सोनम वांगचुक के बयान राष्ट्रीय सुरक्षा और लॉ एंड आर्डर के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि सोनम वांगचुक को जनमत संग्रह की मांग करके जहर फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

एसजी ने वांगचुक के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इलाके को ठप करने से रोकना जरुरी है। क्या वांगचुक चाहते हैं कि लद्दाख, नेपाल और बांग्लादेश बन जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वांगचुक युवाओं को आत्मदाह के लिए उकसा रहे थे। ऐसे कामों की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान और चीन से घिरे इलाके में बैठकर कह रहे हैं कि भारतीय सेना कमजोर है। ये बयान काफी आपत्तिजनक हैं। सुनवाई के दौरान 8 जनवरी को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चौरी-चौरा कांड का जिक्र करते हुए कहा था कि हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल तत्काल वापस ले लिया था। आपको याद होगा कि गांधीजी ने भी ऐसा ही किया था।

सिंगापुर एयर शो में वायु सेना की सारंग टीम दिखाएगी साहसिक हवाई कलाबाजियां

चांगी एग्जिबिशन सेंटर में 37 एयरक्राफ्ट का स्टैटिक डिस्प्ले भी शामिल होगा

नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना सिंगापुर एयर शो के दौरान अपनी सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के जरिए स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) ध्रुव को दिखाएगी। चांगी एग्जिबिशन सेंटर में 3 से 8 फरवरी तक होने वाले इस एयर शो में तीन दूसरी इंटरनेशनल डिस्प्ले टीमें भी हवाई परफॉर्मेंस देंगी और इसमें 37 एयरक्राफ्ट का स्टैटिक डिस्प्ले भी शामिल होगा।

दुनिया भर की वायु सेनाएं और डिफेंस कंपनियां एक मंच पर दिखेंगी। भारतीय वायु सेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपने लाल-सफेद 'ध्रुव हेलीकॉप्टरों से सटीक फॉर्मेशन और साहसी हवाई कलाबाजियां करने के लिए जानी जाती है। यह टीम सिंगापुर एयर शो के दौरान सैन्य ऑपरेशन, मानवीय सहायता और आपदा राहत सहित कई तरह के मिशन में एएलएच ध्रुव की ऑपरेशनल वर्सेटिलिटी, फुर्ती और भरोसे को दिखाएगी। तमिलनाडु के सुलूर में 2005 में बनी सारंग

एरोबैटिक टीम पांच ध्रुव हेलीकॉप्टर का बेड़ा चलाती है।

पिछले कुछ सालों में इस टीम ने कई बड़े अंतरराष्ट्रीय एयर शो में हिस्सा लिया है। इसने रूस में इंटरनेशनल एयर शो (2021), दुबई एयर शो (2021 और 2023), बहरीन इंटरनेशनल एयर शो (2024), और 2024 में सिंगापुर एयर शो के पहले संस्करण में प्रदर्शन किया है। सिंगापुर एयर शो दो साल में एक बार होने वाली एशिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी है, जिसमें दुनिया भर की वायु सेनाएं, रक्षा कंपनियां और एविएशन हितधारक एक मंच पर आते हैं।

यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक बातचीत और उद्योग भागीदारी को बढ़ावा देते हुए उन्नत सैन्य और नागरिक उड्डयन प्रौद्योगिकी को दिखाने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म देता है।

एयरोबैटिक डिस्प्ले के अलावा सारंग टीम नियमित तौर पर घरेलू एयर शो में हिस्सा लेती है। इसने मानवीय सहायता और आपदा राहत ऑपरेशन्स में भी अहम भूमिका निभाई है, जिससे भारतीय वायु सेना की वैश्विक प्रतिबद्धता मजबूत हुई है।

आई होम मास्टर कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार इंटीरियर डिजाइन के नाम पर करोड़ों की ठगी

नोएडा। नोएडा में आई होम मास्टर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के माध्यम से घरों और फ्लैटों में इंटीरियर डिज़ाइन का कार्य करने के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक अभियुक्त को थाना सेक्टर-63 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 6 मॉनीटर, 6 सीपीयू, 6 कीबोर्ड एवं 1 मोबाइल फोन बरामद किया है। एडीसीपी सेन्ट्रल नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि थाना सेक्टर-63 पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से आई होम मास्टर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से इंटीरियर कार्य के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त गुड्डू आलम पुत्र मोहम्मद रुस्तम को सेक्टर-63 से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त द्वारा अपनी कंपनी आई होम मास्टर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से लगभग 20 व्यक्तियों के साथ इंटीरियर कार्य के नाम पर अनुबंध कर उनसे कुल लगभग 2 करोड़ रुपये वसूले गए। अभियुक्त ग्राहकों को झूठे आश्वासन देकर कार्य प्रारंभ नहीं करता था और पैसे वापस मांगने पर उन्हें गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देता था। इसके अतिरिक्त, ग्रेटर नोएडा स्थित एक फ्लैट के इंटीरियर कार्य के लिए करीब 10 लाख रुपये लेकर भी कार्य पूरा नहीं किया तथा धन वापस मांगने पर धमकियां और अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक पीड़ित द्वारा थाना सेक्टर-63 पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। जांच के दौरान जालसाजी की पुख्ता जानकारी मिलने पर पुलिस ने आई होम मास्टर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर गुड्डू आलम

पुत्र मोहम्मद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था। एडीसीपी ने बताया कि जांच में अब तक यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्तों द्वारा संबंधित कंपनी के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों से करोडों रुपये की धनराशि प्राप्त की गई। इस संबंध में अन्य पीड़ितों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त गुड्डू आलम ने पूछताछ में बताया कि वह वर्ष 2021 से आई होम मास्टर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है। वह घरों और फ्लैटों में इंटीरियर डिज़ाइन का कार्य करता है। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह ग्राहकों के साथ इंटीरियर कार्य की कुल लागत पर अनुबंध करता है और अनुबंध के अनुसार घर/फ्लैट मालिक से कुल राशि का लगभग 50-60 प्रतिशत अग्रिम के रूप में प्राप्त करता है। इसके पश्चात वह लेबर को लगाकर घर/फ्लैट में तोड़फोड़ कराता है और इसी दौरान यदि कोई अन्य ग्राहक मिल जाता है तो उससे भी पैसे लेकर कार्य में व्यवधान डालता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि ग्राहक किसी अन्य इंटीरियर डिज़ाइनर के पास न जाए। अभियुक्त ने यह भी बताया कि वह ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए कुछ कार्य पूरे कर उनके सोशल मीडिया प्रचार का उपयोग करता है तथा फोन द्वारा जनता को भरोसा दिलाकर अधिक से अधिक ग्राहक आकर्षित करता है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि ग्राहकों से प्राप्त धनराशि को अभियुक्त अपने निजी शौक में खर्च करता है।

अंतर्राज्यीय मोबाइल स्नेचिंग और दो-पहिया वाहन चोरी के दो शातिर बदमाश गिरफ्तार

नोएडा। थाना फेस-वन पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोबाइल फोन स्नेचिंग एवं दो-पहिया वाहन चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों ने वाहन चोरी की दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया है। दोनों बदमाशों के खिलाफ दिल्ली और नोएडा के थानों में विभिन्न आपराधिक मामलों में 32 मुकदमें दर्ज है। डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि थाना फेस-1 पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से मोबाइल फोन स्नेचिंग एवं दो-पहिया वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय 2

अभियुक्त राहुल उर्फ राबर्ट पुत्र रमेश उर्फ बब्बी तथा नावेद पुत्र फल हसन को सेक्टर-8 नोएडा से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया अभियुक्तों के कब्जे व निशानदेही से चोरी की 10 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी व स्नेचिंग मोबाइल फोन की बिक्री से प्राप्त दो हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे पूर्व में रेकी कर मोटरसाइकिल व स्कूटी की चोरी करते थे तथा चोरी किए गए दो-पहिया वाहनों का प्रयोग कर मोबाइल फोन स्नेचिंग भी करते थे।उन्होंने बताया कि अभियुक्तों द्वारा नोएडा, दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र में मोटरसाइकिल व स्कूटी एवं मोबाइल फोनों की चोरी व स्नेचिंग की गई, जिसके संबंध में एनसीआर के विभिन्न थानों में अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि चोरी एवं स्नेचिंग से प्राप्त मोबाइल फोनों को राहगीरों को बेचकर प्राप्त धनराशि को आपस में बांट लिया करते थे व अपने शौक एवं मौज-मस्ती में खर्च कर देते थे। उन्होंने बताया कि अभियुक्त राहुल के खिलाफ 24 तथा नावेद के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं।

संक्षिप्त खबरें

नशे में धुत युवकों ने मां-बेटे के साथ की मारपीट

दादरी। जारचा क्षेत्र के घनुवास गांव में रविवार को नशे में धुत युवकों ने मां-बेटे के साथ मारपीट की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक धनुवास गांव निवासी पुनीत ने बताया कि वह रविवार को गांव में हलवाई की दुकान पर कुछ सामान खरीद रहा था। इसी बीच सोनू और विवेक नशे की हालत में दुकान पर पहुंचे और बिना वजह पुनीत से गाली-गलौज करने लगे। पुनीत ने बताया कि वह चुपचाप वहां से अपने घर आ गया। आरोप है कि इसके बाद दोनों अपने दो अन्य साथियों के साथ उसके घर आ पहुंचे और पुनीत और उसकी मां के साथ मारपीट की। आरोपी धमकी देकर वहां से भाग गए। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर आरोपी सोनू, विवेक, मोहित और प्रशांत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल में वसंत पंचमी उत्सव पर बच्चों ने प्रस्तुति दी

ग्रेटर नोएडा। जीडी गोयंका स्कूल में सोमवार को वसंत पंचमी उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा एक के छात्रों ने अपनी प्रस्तुति से वसंत पंचमी का महत्व बताया और वसंत ऋतु की सुंदरता को रोचक तरीके से पेश किया। कार्यक्रम में बच्चों ने नृत्य, गीत और कविताओं की प्रस्तुति दी। प्रधानाचार्य रेनू सहगल ने उनकी प्रस्तुति की सराहना की और उन्हें बधाई दी।

जापानी कंपनियों ने छात्रों के लिए खोले द्वार

नोएडा। छात्रों को अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एमिटी विश्वविद्यालय ने अहम कदम उठाया है। एमिटी टेक्निकल प्लेसमेंट सेंटर के तत्वावधान में जापान की सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और पर्यावरण क्षेत्र की कई कंपनियों के प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में सेकिशो कॉर्पोरेशन, कुराकावा कंपनी लिमिटेड, रिओन ऑटोमैटिक मशीनरी, निटोकॉर्प सहित अन्य कंपनियों के सीईओ, डायरेक्टर और सीनियर कॉर्पोरेट लीडर्स शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जापान के इबाराकी प्रीफेक्चर (कृषि विभाग) के सकाई हिरो छात्रों की परीक्षा ली है जिसमें से कई छात्रों को सलेक्ट किया गया है। आगे का सलेक्शन प्रोसीजर जारी है।

शिक्षा प्रेरणा सम्मान से किया सम्मानित

दादरी। समाज में शिक्षा से वंचित बच्चों के जीवन में उजाला लाने के उद्देश्य से किए गए प्रेरणादायक कार्यों के लिए नगर के रेलवे रोड स्थित स्थित किसान यूनियन के कार्यालय पर डॉ. देवेंद्र कुमार नागर को शिक्षा प्रेरणा सम्मान से सम्मानित किया गया। किसान मजदूरों एवं झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें, स्कूल ड्रेस और बैग उपलब्ध कराकर शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर अजीत प्रधान, सरजीत सिंह , जागेश कुमार, कपिल प्रधान, महेंद्र प्रधान, अरुण नागर, मनोज नागर उपस्थित रहे।

सुविधाओं की मांग को लेकर प्राधिकरण पर प्रदर्शन

ग्रेटर नोएडा। ग्राम कासना नटकी मढ़ैया की मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति ने सोमवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर प्रदर्शन किया। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश चौहान ने कहा कि वर्ष 1990 में गांव के अधिग्रहण के बाद से आज तक ग्राम कासना नटकी मढ़ैया का कोई भी प्रतिनिधित्व जिला पंचायत अथवा क्षेत्र पंचायत में नहीं है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधीन होने के बावजूद गांव में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। इस मौके पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अक्षित शर्मा, भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (मजदूर सभा) रोहताश शर्मा, जिलाध्यक्ष पुलकित सिंगल, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा संजीव नायक, नीरज शर्मा, नदीम, विवेक, संजीव कुमार, जिला उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

विदाई समारोह में 12वीं के छात्रों को दी भावभीनी विदाई

नोएडा। सेक्टर-91 में स्थित पंचशील बालक इंटर कॉलेज में कक्षा 12 वीं के छात्रों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। प्रशासनिक अधिकारी नावेद अली ने विद्यार्थियों को अनुशासन, परिश्रम और नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने की सीख दी। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 11 वीं के छात्रों ने सीनियर छात्रों के सम्मान में मनोरंजक गतिविधियां प्रस्तुत की। कक्षा 12 वीं के छात्रों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए विद्यालय और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। यश कुमार ने स्टूडेंट ऑफ ईयर, अभय प्रताप ने मिस्टर पंचशील, अनुराग ने ऑल राउंडर, प्रदीप अधिकारी को मिस्टर जीनियस, रौशन कुमार को मिस्टर फेयरवेल और सुजल कुमार को मिस्टर हार्डवर्किंग का सम्मान दिया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ नीरज टंडन ने सभी छात्रों के उज्ज्वल भविष्य, सफलता एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

वाहन की टक्कर से घायल फैक्टरीकर्मी ने दम तोड़ा

नोएडा। सेक्टर-62 में 11 दिसंबर को अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल फैक्टरीकर्मी की उपचार के दौरान मौत हो गई। उसकी पत्नी ने रविवार को अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जिला रायबरेली के जमुनीपुर चरूहार मजरे गांव की रहने वाली नीलम ने पुलिस को बताया कि उसके पति आशीष नोएडा सेक्टर-63 स्थित फैक्टरी में काम करते थे। वह 11 दिसंबर की रात करीब आठ बजे सेक्टर-62 यूटर्न से होते हुए जा रहे थे। अज्ञात वाहन की टक्कर से वह घायल हो गए थे। आशीष का पहले जिला अस्पताल और फिर दिल्ली के सफजदरजंग अस्पताल में उपचार कराया गया। बीते दिनों वहां से गांव ले जाते समय रास्ते में आशीष की तबीयत खराब हो गई। परिजनों ने सैफई के अस्पताल में उनको भर्ती कराया। वहां पर आशीष की मौत हो गई। शव का अंतिम संस्कार करने के बाद पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि अज्ञात वाहन के चालक की पहचान हो सके।

सोसाइटी के बेसमेंट में सीवर का पानी भरा, बिल्डर पर जुर्माना

ग्रेटर नोएड। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित अजनारा होम्स सोसाइटी के बेसमेंट में सीवर का पानी भरने पर बिल्डर प्रबंधन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा कचरे का निस्तारण न करने पर भी चार लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। प्राधिकरण ने सोसाइटी में रखरखाव की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसी प्रबंधन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है।

प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक सोसाइटी को पूर्व में नोटिस जारी करने और पांच लाख का जुर्माना लगाने के बाद भी एसटीपी का संचालन नहीं किया गया। परिसर में प्रतिदिन 1.15 एमएलडी सीवरेज उत्सर्जित होता है, जो बिना शोधित किए नाले में बहाया जा रहा है। सोसाइटी के लोगों की शिकायत पर सीवर विभाग की टीम ने रविवार को मौके पर जाकर निरीक्षण किया तो बेसमेंट में दो से तीन फीट पानी भरा हुआ था। परिसर में भूजल का अनाधिकृत रूप से दोहन होता मिला। इसका उपयोग सफाई और उद्यान के कार्यों में हो रहा था। इस सोसाइटी में 2300 परिवार रहते हैं। सीवर विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक सन्नी यादव ने बताया कि एसटीपी का संचालन न होने और बेसमेंट में पानी भरने पर बिल्डर प्रबंधन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी चार लाख 3200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। नियमानुसार अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाली संस्थाओं को खुद निस्तारण करना होता है। बीते माह निरीक्षण के दौरान एसटीपी चालू न मिलने पर 25 सोसाइटियों पर पांच- पांच लाख रुपये के हिसाब से पौने दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। एसटीपी के बारे में जानकारी मांगी दरअसल ग्रेटर नोएडा के उच्चाधिकारियों को शिकायत मिली है कि शहर की कुछ बिल्डर सोसाइटियों में एसटीपी चालू नहीं हैं।

घरों से निकलने वाला गंदा पानी शोधित किए बिना नालों में बहाया जा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए सीवर विभाग ने ग्रेटर नोएडा ईस्ट और वेस्ट इलाके स्थित 220 बिल्डर सोसाइटी को नोटिस जारी कर एसटीपी की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है।

> बिल्डर सोसाइटी से निकलने वाले सीवरेज को शोधित करने के लिए एसटीपी को चालू करना अनिवार्य है। इसकी व्यवस्था बिल्डर को खुद करनी होती है। सीवरेज को शोधित किए बिना नाले में बहाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सभी सोसाइटियों की जांच कराई जाएगी।
>
> *- रवि कुमार एनजी, सीईओ, ग्रेटर नोएडा*

कैंसर से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा

ग्रेटर नोएडा। जिम्स की ओर से चार फरवरी को बिसरख स्थित सीएचसी में मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया जाएगा। बताया गया कि तंबाकू और शराब के सेवन से मुंह और गर्दन के कैंसर का खतरा होता है। संस्थान में प्रतिदिन मुंह और गर्दन की समस्या वाले 100 से अधिक मरीज पहुंचते हैं। निदेशक डॉ. बिग्रेडियर राकेश गुप्ता ने बताया कि सिर और गर्दन के कैंसर के मूल्यांकन और रोकथाम के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिम्स के ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉ. हुकुम सिंह ने बताया कि यदि जांच के बाद किसी मरीज को मुंह और गर्दन के कैंसर का पता चलता है, तो सामान्य और लेजर दोनों सर्जरी विधियों का उपयोग करके सर्जरी की जाती है। तंबाकू से संबंधित कैंसर, जीवनशैली के जोखिम कारकों, प्रारंभिक चेतावनी के संकेतों और रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने में सार्वजनिक जागरुकता की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

रेस्टोरेंट संचालिका से बदसलूकी

नोएडा। सेक्टर-18 स्थित रेस्टोरेंट की संचालिका ने कार सवार युवकों पर गाली-गलौज, धमकी देने और परेशान करने का आरोप लगाया। दावा है कि आरोपी जानबूझकर रेस्टोरेंट के बाहर लघुशंका करते हैं। महिला ने इसका वीडियो भी पुलिस को उपलब्ध कराया। पीड़िता ने सेक्टर-20 थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी है। महिला ने पुलिस को बताया कि वह बीते दो सालों से सेक्टर-18 में शाकाहारी रेस्टोरेंट का संचालन कर रही हैं। बीते कुछ दिनों से रेस्टोरेंट के पास स्थित कैफे के कुछ ग्राहक बार-बार उनके रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार करते हैं। शुक्रवार रात करीब साढ़े आठ बजे कार सवार युवक फिर से उनके रेस्टोरेंट के बाहर आए और तेज आवाज में गालियां देने लगे। इससे वहां मौजूद ग्राहक और कर्मचारी डर गए। जब रेस्टोरेंट के कर्मचारी ने युवकों को ऐसा करने से मना किया तो उनमें से एक युवक ने कार से कोई वस्तु निकालकर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान कर्मचारी खुद को बचाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर भागे। इससे रेस्टोरेंट में मौजूद महिला स्टाफ और ग्राहक डर गए। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह घटना उनके लिए अपमानजनक और असुरक्षित स्थिति पैदा करने वाली है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद है। घटना का, जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें रेस्टोरेंट के बोर्ड पर एक व्यक्ति पेशाब करता दिख रहा

ऑपरेशन सेफ स्ट्रीट्स : पुलिस ने 67,480 वाहनों का किया चालान, शराब पीकर वाहन चलाने वालें 661 लोगों पर की कार्रवाई

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में ऑपरेशन सेफ स्ट्रीट्स के तहत 1330 स्थानों पर विशेष अभियान चलाकर 67480 वाहनों का चालान किया। वहीं मदिरा पीकर वाहन चलाने वाले 661 लोगों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। गौतमबुद्धनगर पुलिस

कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर जनपद के तीनों जोन (नोएडा, सेन्ट्रल नोएडा व ग्रेटर नोएडा) में बीती 23 जनवरी से 31जनवरी 2026 तक शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस ने अभियान चलाया। इस अभियान में कुल 67480 वाहनों का चालान किया गया, जिसमें ई-चालान भी सम्मिलित है। वहीं नशे की हालत में पाए गए 661 वाहन चालकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में तथा 482 वाहनों को सीज की कार्रवाई की गई। डीसीपी नोएडा जोन यमुना प्रसाद के नेतृत्व में नोएडा जोन में ऑपरेशन सेफ स्ट्रीट्स अभियान 438 स्थानों पर चलाया गया। जिसमें कुल 30818 वाहन चेक किए गए। पुलिस टीमों द्वारा नियमों का पालन न करने वाले 9955 वाहनों के विरूद्ध ई-चालान की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान 267 वाहनों को सीज किया गया। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 4006 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 292 बीएनएस तथा 110 व्यक्तियों के विरुद्ध बीएनएसएस के विभिन्न धारा के तहत विधिक कार्रवाई की गई।

इसी तरह डीसीपी सेन्ट्रल नोएडा जोन शक्ति मोहन अवस्थी के नेतृत्व में सेन्ट्रल नोएडा जोन में 445 स्थानों पर चेकिंग करते हुए कुल 16871वाहन चेक किए गए। पुलिस टीमों द्वारा नियमों का पालन न करने वाले 2947 वाहनों के विरुद्ध ई-चालान की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान 22 वाहनों को सीज किया गया। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 966 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 292 बीएनएस तथा 131 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। वहीं डीसीपी ग्रेटर नोएडा जोन साद मियां खान के नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा जोन में 378 स्थानों पर चेकिंग करते हुए कुल 17333 वाहन चेक किए गए। पुलिस टीमों द्वारा नियमों का पालन न करने वाले 3820 वाहनों के विरूद्ध ई-चालान की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान 75 वाहनों को सीज किया गया। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 512 व्यक्तियों के धारा 292 बीएनएस तथा 19 व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धारा के अंतर्गत विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई। इसके अलावा डीसीपी यातायात मनीषा सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा नियमों का पालन न करने वाले 50758 वाहनों के विरुद्ध ई-चालान की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान 118 वाहनों को सीज किया गया।

अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डॉ. राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि ऑपरेशन सेफ स्ट्रीट्स अभियान के दौरान नशे की अत्यधिक अवस्था में वाहन चलाते पाए गए 30 व्यक्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चलाने से रोका गया तथा उन्हें सकुशल उचित माध्यम से घर पहुंचाया। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नशीले पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाएं तथा स्वयं एवं अन्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए यातायात नियमों का पालन करें।

केंद्रीय बजट 2026-27 दिल्ली के लिए विकास और रोजगार का उत्कृष्ट रोडमैप : मुख्यमंत्री

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय बजट 2026-27 को "अगली पीढ़ी का बजट" बताते हुए कहा कि यह बजट स्वास्थ्य, पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों को रोजगार सृजन से जोड़ता है और दिल्ली के समग्र विकास की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने केंद्रीय बजट 2026-27 को दिल्ली के लिए विकास और रोजगार का उत्कृष्ट रोडमैप बताया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बजट ₹संतुलित₹ है और इसमें देश की महिलाओं और युवाओं सहित हर वर्ग को अवसर प्रदान किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में आया यह बजट आर्थिक मजबूती के साथ सामाजिक संतुलन का भी बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने वित्त मंत्री द्वारा बताए गए तीन कर्तव्यों की भी सराहना करते हुए कहा कि यह बजट युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए नए अवसर पैदा करेगा और भारत की प्रगति को नए आयाम तक ले जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट तीन अहम जिम्मेदारियों पर आधारित है। पहली देश की आर्थिक गति को तेज करना और उसे स्थिर बनाए रखना। दूसरी, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, ताकि हर नागरिक विकास का हिस्सा बन सके और तीसरी, 'सबका साथ, सबका विकास' के विचार को जमीन पर उतारना।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में महिलाओं की शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में लड़कियों के छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही दिल्ली को केंद्रीय बजट में 1300 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन मिला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रस्तावित नरेला शिक्षा केंद्र को इस साल के केंद्रीय बजट में घोषित पांच नए विश्वविद्यालय टाउनशिप में शामिल करने का प्रयास करेगी।

उन्होंने बताया कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'कंटेंट क्रिएशन लैब्स' स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। दिल्ली सरकार इस पहल के तहत दिल्ली के सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों को भी जोड़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली बजट प्रावधानों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेगी, उन्होंने कहा कि पूंजी हस्तांतरण के लिए राज्यों को विशेष सहायता पिछले बजट में 6,275 करोड़ से बढ़कर 2026-27 के बजट में 15,380 करोड़ रुपये हो गई है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रायोजित योजनाओं का बजट बढ़ाकर 13,611 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके तहत दिल्ली में संचालित 39 कार्यक्रमों के लिए पूरा हिस्सा दिल्ली को मिलेगा।

रेखा गुप्ता ने दिल्ली पुलिस के लिए बजट बढ़ाकर 12,500 करोड़ रुपये किए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपनी परियोजनाओं के लिए धन सुरक्षित करने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। पूरे बजट को देखते हुए यह दिल्ली के लिए एक उत्कृष्ट बजट है, जो रोजगार, विकास और शहर के समग्र हितों को साधता है। रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट देश के हर वर्ग को भरोसा देता है। यह गरीबों को सहारा देने वाला, युवाओं को अवसर देने वाला और महिलाओं के सम्मान व सशक्तिकरण का बजट है। यह देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक साफ और मजबूत रोडमैप पेश करता है।

दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल परियोजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें दिल्ली से वाराणसी तक का मार्ग भी शामिल है। इससे यात्रा आसान होगी, पर्यटन बढ़ेगा, व्यापार को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही, दिल्ली की पहचान बड़े आर्थिक और परिवहन केंद्र के रूप में और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि दिल्ली सरकार विकसित भारत 2047 और विकसित दिल्ली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली सरकार हर योजना को जमीन पर उतारेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इसका लाभ दिल्ली के हर नागरिक तक पहुंचे।

स्कूल फीस को विनियमित करने वाला नया कानून 2025-26 में लागू नहीं होगा : दिल्ली सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में निजी स्कूलों में फीस को विनियमित करने वाला नया कानून शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में लागू नहीं किया जाएगा। यह बयान न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ के समक्ष दिया गया, जो दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने पीठ को बताया कि मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में यह कानून लागू नहीं किया जाएगा। पीठ ने कहा, "एस वी राजू द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को देखते हुए... कि यह कानूनी व्यवस्था 2025-26 से लागू नहीं होगी, आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।" इसने सभी मुद्दों को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उठाने के लिए विकल्प दिया, जो 2025 के अधिनियम और उसके बाद के नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। उच्चतम न्यायालय उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें उच्च न्यायालय के आठ जनवरी के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं, जिसमें यहां के निजी स्कूलों को शुल्क विनियमन समितियों का गठन करने का निर्देश देने वाली अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन ऐसी समितियों के गठन के लिए समयसीमा बढ़ा दी गई थी। सुनवाई के दौरान, मामले में पेश हुए वकीलों में से एक ने कहा कि उच्च न्यायालय को इस मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए क्योंकि इसमें कई स्कूल और लाखों बच्चे शामिल हैं। पीठ ने कहा, "उच्च न्यायालय को इसकी जानकारी है। यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उच्च न्यायालय इससे अनभिज्ञ है और केवल हमें ही इसकी जानकारी है।" जब एक अन्य वकील ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 31 मार्च से पहले उच्च न्यायालय में होनी चाहिए, तो पीठ ने कहा कि पक्षकार उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं के शीघ्र निस्तारण के लिए अनुरोध कर सकते हैं। याचिकाओं पर 19 जनवरी को सुनवाई करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने कानून को लागू करने में दिल्ली सरकार द्वारा चुने गए समय को लेकर सवाल उठाए थे।

धौलाकुआं बीएमडब्ल्यू हादसा : पटियाला हाउस कोर्ट ने गगनप्रीत को चार्जशीट की कॉपी सौंपी

नई दिल्ली। दिल्ली के धौलाकुआं बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत कौर को चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। आरोपी गगनप्रीत कौर सोमवार को कोर्ट में पेश हुईं, जहां उन्होंने यह आदेश प्राप्त किया। कोर्ट ने यह निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी तय की है। इस तारीख को चार्जशीट की विस्तृत जांच यानी स्क्रूटनी की जाएगी। यह मामला पिछले साल 14 सितंबर 2025 को दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। उस दिन वित्त मंत्रालय में उप सचिव पद पर तैनात 52 वर्षीय नवजोत सिंह अपनी पत्नी संदीप कौर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थे। धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन के पास गगनप्रीत कौर द्वारा चलाई जा रही बीएमडब्ल्यू कार ने तेज रफ्तार में उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में नवजोत सिंह को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी सहित अन्य लोग भी घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गगनप्रीत कौर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (जो हत्या के समकक्ष गैर-इरादतन हत्या से संबंधित है) के अलावा धारा 281, 125बी और 238ए के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का आरोप है कि आरोपी ने दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को समय पर उचित चिकित्सा सहायता नहीं पहुंचाई, जिसके कारण 'गोल्डन आवर' का समय व्यर्थ गया और नवजोत सिंह की जान बचाई जा सकती थी। चार्जशीट करीब 400 पन्नों की है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और अन्य सबूत शामिल हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और आरोपी को समन जारी किया था। अब कोर्ट ने चार्जशीट की कॉपी देने का आदेश देकर मामले को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ किया है।

विजेंद्र गुप्ता ने किया विधायकों के वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को संत परमानंद अस्पताल में मौजूदा विधायकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गुप्ता ने कहा कि स्वस्थ जनप्रतिनिधि ही सशक्त संस्थानों की नींव होते हैं और बेहतर जनसेवा सुनिश्चित करते हैं।

यह स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम आज से प्रारंभ होकर 14 फरवरी तक चलेगा और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की वर्तमान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इस अवसर पर विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि यह पहल दिल्ली विधानसभा के सभी सदस्यों के साथ संवाद और सहमति के माध्यम से एक नई शुरुआत के रूप में आरंभ की गई है। आज से औपचारिक रूप से वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन छह विधायक अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराएंगे।

अध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम के प्रथम दिन सूर्य प्रकाश खत्री, पूनम भारद्वाज एवं अनिल झा ने स्वास्थ्य परीक्षण में भाग लिया। बाकी तीन विधायकों ने अपने निजी कारणों से जांच में भाग नहीं लिया। उन्होंने इस पहल को एक सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को निरंतर जनता के बीच सक्रिय रहना पड़ता है, ऐसे में उनके लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रभावी जनसेवा तभी संभव है जब जनप्रतिनिधि शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सक्षम और भावनात्मक रूप से सकारात्मक हों।

अध्यक्ष ने कहा कि यह कार्यक्रम दो सप्ताह यानी, 2 से 14 फरवरी तक चलेगा और प्रतिदिन पांच विधायक उत्साहपूर्वक इसमें भाग लेंगे। उन्होंने विशेष रूप से 40 वर्ष की आयु के बाद नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस आयु वर्ग में निवारक स्वास्थ्य देखभाल और भी अधिक आवश्यक हो जाती है।

गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में प्रारंभ किया गया यह स्वास्थ्य परीक्षण जागरूकता अभियान एक अनूठी पहल है। उन्होंने हाल ही में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन का उल्लेख करते हुए बताया कि वहां इस विषय पर चर्चा हुई थी तथा दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने इस पहल की प्रस्तुति दी थी। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्षों ने दिल्ली मॉडल में गहरी रुचि दिखाई और कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

अध्यक्ष ने विश्वास व्यक्त किया कि दिल्ली विधानसभा द्वारा की गई यह पहल देश की अन्य राज्य विधानसभाओं द्वारा भी अपनाई जाएगी। उन्होंने अन्य विधानसभाओं के अध्यक्षों से अपील की कि वे भी अपने-अपने राज्यों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ करें, ताकि वे अधिक ऊर्जा, सामर्थ्य और प्रभावशीलता के साथ जनसेवा कर सकें।

किशोर की हत्या के प्रयास में चार नाबालिग पकड़े गए

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने चार नाबालिगों को हिरासत में लेकर पटेल नगर इलाके में हत्या के प्रयास के एक मामले को सुलझाने का दावा किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह घटना 28 जनवरी को पटेल नगर में दयानंद मॉडल पब्लिक स्कूल के पास उस वक्त हुई, जब 16-वर्षीय एक लड़के पर कथित तौर पर चाकू से हमला किया गया। वह नाबालिग उस वक्त अपने पिता की स्कूल वैन में बैठा था।

पुलिस अधिकारी ने बताया, "लड़के का पिता उस समय दूसरे स्कूल से छात्रों को लाने गया था। पीड़ित का पांच-छह दिन पहले कुछ लड़कों के साथ निजी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके दौरान उसे धमकी दी गई थी।" अधिकारी ने बताया कि 28 जनवरी को दोपहर दो बजे पीड़ित के परिचित तीन-चार लड़के मौके पर पहुंचे और कथित तौर पर वाहन के खिड़की के शीशे को तोड़ना शुरू कर दिया। उनके मुताबिक, लड़के ने वैन से उतरकर जब भागने की कोशिश की तो हमलावरों में से दो ने उसे पकड़ लिया, जबकि एक अन्य ने कथित तौर पर उसे जान से मारने के इरादे से उसकी पीठ पर चाकू से दो वार किये। इसके बाद हमलावर भाग गए। घायल ने अपने पिता को इस बारे में सूचित किया, जिसके बाद उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। चोटों की गंभीरता को देखते हुए उसे राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया और आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई। पुलिस ने सूचना के आधार पर आनंद पर्वत के रामजस पार्क में छापा मारा और चार नाबालिगों को पकड़ लिया। अधिकारी ने बताया, "पूछताछ के दौरान नाबालिगों ने हमले में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। उनके पास से अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।"

दिल्ली पुलिस की सतर्क पेट्रोलिंग से बड़ी सफलता, 3 मोबाइल जब्त, शातिर गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सतर्क पेट्रोलिंग से एक स्नैचर को छीने हुए मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। हालांकि, दो आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए हर पुलिस स्टेशन के तहत कई पेट्रोलिंग टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों को अच्छे से ब्रीफ किया गया और उन्हें पूरी सतर्कता के साथ पेट्रोलिंग करने के लिए कहा गया, खासकर सुबह-सुबह, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। पेट्रोलिंग का मकसद सिर्फ अपराध रोकना नहीं है, बल्कि इलाके में सक्रिय अपराधियों पर लगातार नजर रखना भी है। ऐसी ही एक पेट्रोलिंग के दौरान, 27 जनवरी को पीपी सिधिपुरा के कांस्टेबल प्रताप इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे। रानी झांसी रोड, मॉडल बस्ती रेड लाइट के पास, उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल कार से टकरा गई। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचने लगी, तीनों बाइक सवार घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे। कांस्टेबल प्रताप ने तुरंत उनका पीछा किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों में से एक को पकड़ लिया, जबकि बाकी दो मोटरसाइकिल लेकर भागने में सफल रहे। पकड़े गए युवक की पहचान रितिक उर्फ कलवा, उम्र 22 साल, निवासी नबी करीम, पहाड़गंज, दिल्ली के रूप में हुई। रितिक की तलाशी लेने पर उसके पास से तीन मोबाइल फोन बरामद हुए, जिससे उसके मोबाइल छीनने के मामलों में शामिल होने की पुष्टि हुई। पूछताछ में रितिक ने बताया कि वह अपने साथियों वसीम और सलीम के साथ मिलकर लगभग 10–12 दिन पहले आनंद पर्वत इलाके से एक ग्रे रंग की बजाज पल्सर मोटरसाइकिल चुराई थी। चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके उन्होंने थाना मोती नगर और लाहौरी गेट के इलाकों में मोबाइल फोन छीनने की वारदातें की थीं। रितिक को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी फरार साथियों वसीम और सलीम को पकड़ने के लिए जांच जारी है। बरामद मोबाइल फोन इस प्रकार हैं: पहला, ओप्पो मोबाइल फोन, जो थाना मोती नगर के चोरी मामले से संबंधित है। दूसरा, आईटेल मोबाइल फोन, जो थाना लाहौरी गेट के छीनने के मामले से जुड़ा है। तीसरा, लावा मोबाइल फोन, जिसके संबंध में आरोपी कोई मालिकाना दस्तावेज पेश करने या संतोषजनक जवाब देने में असफल रहा। पुलिस अब बाकी फरार आरोपियों को पकड़ने और बरामद मोबाइल फोन के सही मालिक का पता लगाने के लिए आगे जांच कर रही है।

निजी अस्पतालों की 'लूट' पर राज्यसभा में गरजीं स्वाति मालीवाल, कहा- 'इलाज नहीं, यहां सिर्फ बिलिंग चल रही है'

नई दिल्ली। देश में निजी अस्पतालों की मनमानी और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर हो रही 'व्यावसायिक लूट' का मुद्दा आज संसद में गूंजा। दिल्ली से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने शून्यकाल के दौरान निजी अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच चल रहे कथित गठजोड़ पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि 'क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट' को पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू किया जाए ताकि मरीजों को राजस्व का साधन समझने की मानसिकता पर लगाम लग सके। सदन को संबोधित करते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि आज निजी अस्पताल सेवा केंद्र के बजाय फाइव स्टार होटल बन गए हैं। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा, ₹अस्पतालों में डीलक्स, प्रीमियम और सुइट जैसे कमरों का किराया बड़े होटलों से भी अधिक वसूला जा रहा है। विडंबना यह है कि जब कोई मरीज आपात स्थिति में पहुंचता है, तो डॉक्टर उसकी नब्ज टटोलने से पहले यह पूछते हैं कि बीमा है या नहीं और जेब में पैसे कितने हैं। सांसद स्वाति मालीवाल ने बिलिंग व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि थर्मामीटर, दस्ताने, मास्क और सैनिटाइजर जैसी बुनियादी चीजों के भी भारी-भरकम दाम बिल में जोड़ दिए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मरीजों को जानबूझकर महंगी ब्रांडेड दवाइयां लिखी जाती हैं और अनावश्यक टेस्ट करवाए जाते हैं, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार कर्ज के दलदल में फंस जाता है। सांसद ने अंत में भावुक अपील करते हुए कहा कि यह देश के आम नागरिक की गरिमा और स्वास्थ्य के अधिकार का सवाल है। अब समय आ गया है कि सरकार निजी स्वास्थ्य क्षेत्र की जवाबदेही तय करे। मालीवाल ने केवल अस्पतालों को ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कंपनियां प्रीमियम तो हर साल बढ़ा देती हैं, लेकिन क्लेम देने के वक्त छोटी-छोटी शर्तों और 'छिपे हुए नियमों' का हवाला देकर दावे खारिज कर देती हैं। उन्होंने मांग की कि बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली और प्रीमियम बढ़ोतरी पर सरकार की सख्त निगरानी होनी चाहिए। संसद में अपनी बात रखते हुए स्वाति मालीवाल ने याद दिलाया कि वर्ष 2010 में 'क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट' पारित किया गया था।

गहने चुराने के आरोप में घरेलू सहायिका गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली के द्वारका में अपने नियोक्ता के घर से सोने और हीरे के गहने चुराने के आरोप में एक घरेलू सहायिका को मध्यप्रदेश के दमोह से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दमोह निवासी घरेलू सहायिका लक्ष्मी रानी बंसल के पास से सोने की दो चूड़ियां, सोने की बालियों की एक जोड़ी, हीरे की बालियों की एक जोड़ी, झुमके के साथ एक सोने का पेंडेंट और झुमके के साथ एक सोने का हार बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार, इस संबंध में 22 जनवरी को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद द्वारका के सेक्टर-23 थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धारा के तहत एक ई-प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि चोरी की घटना सामने आने के तुरंत बाद बंसल अपने किराए के मकान से लापता हो गई थी, जिससे पुलिस को उस पर संदेह हुआ और उसकी पहचान संदिग्ध के रूप में की गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बंसल के फोन कॉल रिकॉर्ड के विश्लेषण से पता चला कि वह मध्यप्रदेश में अपने पैतृक स्थान चली गई है। पुलिस ने बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर, मध्यप्रदेश में स्थानीय पुलिस की सहायता से, टीम ने दमोह जिले के गांव पथरिया में उसके घर पर छापा मारा।

दिल्ली में सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस और सुजुकी के बीच एमओयू

नई दिल्ली। राजधानी में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक अहम पहल की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच सड़क सुरक्षा शिक्षा को नया आयाम देने के लिए सोमवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। पुलिस मुख्यालय में संपन्न इस एमओयू साइनिंग समारोह में दिल्ली के पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा और विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) नीरज ठाकुर मौजूद रहे। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पहल को जनहित में पुलिस और कॉरपोरेट क्षेत्र के बीच प्रभावी सहयोग का बेहतरीन उदाहरण बताया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक मुख्यालय) सत्यवीर कटारा ने जबकि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया की ओर से कार्यकारी अधिकारी (एचआर व बिजनेस डेवलपमेंट) देवाशीष हांडा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया और वैल्यू लाइफ फाउंडेशन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस रणनीतिक साझेदारी के तहत बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क के उन्नयन, रखरखाव और बेहतर संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पार्क में सड़क सुरक्षा से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि इस सहयोग में प्रशिक्षण ढांचे को बेहतर बनाना, आधुनिक सड़क सुरक्षा उपकरणों की स्थापना, इंटरैक्टिव ट्रेनिंग मॉड्यूल विकसित करना, साइन बोर्ड और जागरूकता सामग्री को मजबूत करना तथा स्कूली बच्चों और आम लोगों के लिए नियमित सड़क सुरक्षा कार्यक्रम शामिल हैं। वैल्यू लाइफ फाउंडेशन इस परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में काम करेगी और ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क के दैनिक संचालन व मानव संसाधन प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगी। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा शिक्षा और समुदाय की भागीदारी को लेकर नए विचारों पर भी चर्चा हुई। पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने सभी हितधारकों से प्रतिबद्धता और दूरदृष्टि के साथ काम करने का आह्वान करते हुए कहा कि ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क को एक आदर्श सड़क सुरक्षा शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिसे देशभर में अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हर यात्री के लिए सुरक्षित भविष्य बनाना ही इस पहल का लक्ष्य है। इस सहयोग से पारंपरिक ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क को आधुनिक और इंटरैक्टिव लर्निंग हब में बदला जाएगा, जहां तकनीक, व्यावहारिक प्रशिक्षण और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के जरिए स्कूली बच्चों, युवा चालकों और आम नागरिकों को ट्रैफिक नियमों, रक्षात्मक ड्राइविंग और जिम्मेदार सड़क व्यवहार के प्रति जागरूक किया जाएगा।

संपादकीय

कांग्रेस की समस्या

'बचाओ' या 'वापस लाओ' जैसे नारे लोगों का ध्यान खींचने के लिहाज से हमेशा अपर्याप्त साबित हुए हैं। कांग्रेस की समस्या यह है कि हाल-फिलहाल में वह भविष्य का कोई सपना या लोक-लुभावन कार्यक्रम पेश करने में नाकाम रही है। मजदूर अधिकार के सवाल पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस की सही दिशा में पहल है, बशर्ते यह मुद्दा उसकी क्षणिक चिंता बन कर ना रह जाए। कामकाजी वर्ग की बढ़ती मुश्किलें और उसके घटते अधिकार आज असल मुद्दे हैं, जिनकी मुख्यधारा राजनीति में मजबूत वकालत की जरूरत है। मनरेगा खत्म कर उसकी जगह जी राम जी कानून लागू करने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस ने इस पर ध्यान दिया है। चूंकि मनरेगा को कांग्रेस नेतृत्व अपनी बड़ी उपलब्धि मानता था, इसलिए उस पर हुए प्रहार से वह भी विचलित हुआ। तब पार्टी ने 'मनरेगा बचाओ' आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। अब पार्टी उसे मजदूर अधिकार के बड़े दायरे से जोड़ने का संकेत दे रही है।

इस मसले पर पार्टी समग्र सोच विकसित कर सके और उसके आधार पर संगठन एवं संघर्ष की दीर्घकालिक योजना बनाए, तो उससे कांग्रेस को आज के दौर में एक खास पहचान मिल सकती है। मगर पार्टी नेतृत्व की मुश्किल यह है कि वह संयम के साथ किसी एक मुद्दे पर नहीं टिकता। जो भी मुद्दा वह उठाता है, उसके पीछे मकसद अपनी पूर्व सरकारों के रिकॉर्ड को मोदी सरकार से बेहतर दिखाने तक सीमित रह जाता है। राफेल से लेकर ए-2 (यानी दो घरानों की मोनोपॉली) पर आक्रामक रुख अपनाने के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी जातीय जनगणना एवं 1990 के दशक के मंडल-कालीन विमर्श में जा सिमटे।

उसी क्रम में 'संविधान बचाओ' का झंडा उन्होंने उठाया। फिर 'वोट चोरी' उनका पसंदीदा मसला बना। अब मनरेगा की वापसी उनका प्रिय विषय बना है। जबकि समझने की बात यह है कि 'बचाओ' या 'वापस लाओ' जैसे नारे लोगों का ध्यान खींचने के लिहाज से हमेशा अपर्याप्त साबित हुए है। कांग्रेस की समस्या यह है कि हाल के दशकों में वह भविष्य का कोई सपना या लोक-लुभावन कार्यक्रम पेश करने में नाकाम रही है। ऐसे में आम जन को उसका एजेंडा नकारात्मक मालूम पड़ता है। पार्टी के मजदूर अधिकार सम्मेलन को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाएगा। सवाल यह है कि क्या यहां से कांग्रेस कोई सकारात्मक सोच देश के सामने रख पाएगी। ऐसा होने की संभावना काफी कम दिखाई पड़ रही है।

सहजन के फूलों में नवजीवन का उल्लास

सहजन के फूलों को जब पानी में डुबोया जाता तो वे अपनी कोमलता को त्यागकर पकने के लिए तैयार हो जाते। जैसे जीवन भी तपने पर ही अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। उनकी हल्की कड़वाहट, उनकी मिट्टी की गंध और उनके भीतर बसी हुई मृदुता एक संपूर्ण कविता थी-जिसे सिर्फ स्वाद से ही नहीं, हृदय से भी समझा जा सकता था। सहजन के फूलों की एक अलग ही दुनिया थी-न धूमधाम, न रंगों का जादू, बस सफेदी में लिपटी हुई एक गहरी अनुभूति। वे उन शब्दों की तरह थे, जो बिना किसी शोर के भी भीतर तक असर कर जाते हैं। उनके गिरने का ढंग भी अनूठा था-धीरे-धीरे, बूंद-बूंद की तरह, मानो समय के हाथों में अपनी अंतिम आहुति दे रहे हों। जब हवा सहजन के फूलों को स्पर्श करती तो वे एक अनकही भाषा में झूम उठते। यह भाषा किसी एक की नहीं थी, यह उन सभी की थी, जिन्होंने प्रतीक्षा की पीड़ा को समझा था। एक विरहिणी नायिका की तरह ये फूल अपनी डालियों से अलग होकर भी किसी अदृश्य प्रेम के साथ जुड़े रहते थे। सहजन के फूलों में प्रेम था-एक ऐसा प्रेम, जो सब कुछ सहकर भी विनम्र बना रहता है।

परिचय दास

वसंत की प्रथम आहट के साथ ही सहजन के पेड़ ने अपनी शाखाओं को नवजीवन के उजास से भर लिया। हल्की ठंडी हवा, धूप की धीमी परछाइयां और कोयल की आवाज के बीच सहजन के फूल अपनी नाजुक पंखुड़ियों को खोलने लगे। इन फूलों में एक अलौकिक सादगी थी, जैसे किसी गजल का पहला मिसरा-अनायास, लेकिन भीतर तक स्पंदित कर देने वाला। इन छोटे-छोटे सफेद फूलों की सुगंध में स्मृतियों का एक संसार बसता था। गांव की वह पगडंडी, जहां दुपहरिया की उनींदी हवा में सहजन की डालियां झूलती थीं। उनकी छांव में खेलते बच्चे, दोपहर की थकान से आंखें मूंदकर सुस्ताते किसान और किसी कोने में बैठी कोई स्त्री, जो फूलों को बटोर कर उनकी सब्ज़ी बनाने की सोच रही थी। सहजन का फूल केवल फूल नहीं था, यह किसी विरासत की तरह अगली पीढ़ी को सौंपा जाने वाला एक गीत था-मौन में गाया हुआ लेकिन दिल की गहराइयों तक गूंजता हुआ।

सहजन के फूलों को जब पानी में डुबोया जाता तो वे अपनी कोमलता को त्यागकर पकने के लिए तैयार हो जाते। जैसे जीवन भी तपने पर ही अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। उनकी हल्की कड़वाहट, उनकी मिट्टी की गंध और उनके भीतर बसी हुई मृदुता एक संपूर्ण कविता थी-जिसे सिर्फ स्वाद से ही नहीं, हृदय से भी समझा जा सकता था। सहजन के फूलों की एक अलग ही दुनिया थी-न धूमधाम, न रंगों का जादू, बस सफेदी में लिपटी हुई एक गहरी अनुभूति। वे उन शब्दों की तरह थे, जो बिना किसी शोर के भी भीतर तक असर कर जाते हैं। उनके गिरने का ढंग भी अनूठा था-धीरे-धीरे, बूंद-बूंद की तरह, मानो समय के हाथों में अपनी अंतिम आहुति दे रहे हों। जब हवा सहजन के फूलों को स्पर्श करती तो वे एक अनकही भाषा में झूम उठते। यह भाषा किसी एक की नहीं थी, यह उन सभी की थी, जिन्होंने प्रतीक्षा की पीड़ा को समझा था। एक विरहिणी नायिका की तरह ये फूल अपनी डालियों से अलग होकर भी किसी अदृश्य प्रेम के साथ जुड़े रहते थे। सहजन के फूलों में प्रेम था-एक ऐसा प्रेम, जो सब कुछ सहकर भी विनम्र बना रहता है। कभी-कभी, जब संध्या उतरती तो सहजन के फूलों से भरी डालियां चुपचाप अपने अस्तित्व को देखती रहतीं। जैसे किसी बूढ़े साधु की आंखों में ठहरा हुआ संतोष। वे फूल, जो दिनभर हवा के साथ हंसे थे, अब निशब्द खड़े रहते- स्वीकृति और समर्पण के साथ। वे जानते थे कि उनकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, वे मिट्टी में मिलकर फिर से जन्म लेंगे, किसी और शाखा पर, किसी और ऋतु में।

सहजन के फूलों की यही विशेषता थी- वे जीवन के सबसे सरल, सबसे अल्पकालिक, लेकिन सबसे अर्थपूर्ण हिस्से थे। वे बिना बोले हमें सिखा जाते थे कि सौंदर्य केवल भव्यता में नहीं, सादगी में भी होता है। वे हमें यह भी सिखाते थे कि जो गिरने में भी आनंद पा सके, वही सच्चे अर्थों में खिला हुआ है।

जब भी कोई सहजन के फूलों को देखता, उसे अपने भीतर कोई भूला-बिसरा गीत याद आ जाता। कोई पुरानी चिट्ठी, कोई अनकहा वादा, कोई अधूरा सपना। वे फूल नहीं थे, वे स्मृतियों की छोटी-छोटी नावें थीं, जो समय की नदी में बहती रहती थीं - शांत, निश्चल, लेकिन हर किसी तक पहुंचने वाली। कई बार, मैं सहजन के उन फूलों को देखता और सोचता - क्या जीवन भी ऐसा ही नहीं है? क्या हम सब किसी शाखा पर लगे हुए फूल ही तो नहीं, जिन्हें एक दिन जमीन पर गिर जाना है? और अगर गिरना ही नियति है तो क्यों न गिरते समय भी अपनी सुगंध को बचाए रखें? क्यों न इस यात्रा को भी सुंदर बना दें? शायद यही कारण था कि जब भी सहजन के फूल जमीन पर बिखरते, वे किसी उदासी में नहीं बल्कि एक नृत्य में होते थे। जैसे किसी विदा होती आत्मा की अंतिम प्रार्थना। जैसे किसी प्रेमी की वह चुप्पी, जिसमें कोई शिकायत नहीं, सिर्फ समर्पण होता है।

सहजन के फूल सिर्फ पेड़ पर नहीं खिलते, वे स्मृतियों में भी खिलते हैं। वे बचपन की कच्ची धूप में खिलते हैं, वे मां के हाथों की गर्माहट में खिलते हैं, वे किसी पुरानी धुन में खिलते हैं। वे हवा में बहते हैं, मिट्टी में घुलते हैं और फिर किसी नए वृक्ष की शाख पर उग आते हैं। और इस तरह, सहजन के फूल कभी मरते नहीं। वे हर बार नए स्वरूप में लौटते हैं -उसी सादगी, उसी नमी और उसी अव्यक्त सौंदर्य के साथ। सहजन के फूल चुपचाप खिलते हैं- जैसे किसी कविता की सबसे मृदु पंक्ति जो अर्थों के भार से झुकी हुई नहीं बल्कि हल्की होकर हवा में बहती है। वे किसी भी ऋतु के प्रखर नायक नहीं होते, न वसंत के रंगों में खोए रहते हैं, न पतझड़ की उदासी को ओढ़ते हैं। वे बस आते हैं—धीरे से, संकोच के साथ, जैसे किसी पुरानी धुन का पहला सुर, जिसे केवल वही सुन सकता है, जिसकी स्मृतियों में कोई शांत धूप बची हो।

सहजन के फूलों की सादगी में एक अजीब-सी जटिलता है। वे जितने सीधे दिखते हैं, उतने ही गहरे होते हैं। सफेद, नर्म और हल्की गंध से भरे हुए ये फूल किसी मौन गीत की तरह खिलते हैं -शब्दों से अधिक अनुभव में बहते हुए। हवा उन्हें छूती है और वे बिना किसी प्रतिरोध के बहने लगते हैं। जैसे प्रेम में समर्पण का पहला क्षण, जब सब कुछ स्पष्ट नहीं होता लेकिन महसूसना ही पर्याप्त होता है। सहजन के फूल गिरते नहीं—वे उतरते हैं। धीरे-धीरे, जैसे समय के स्पर्श से पिघलकर धरती की गोद में समा रहे हों। उनकी यात्रा किसी संत की प्रार्थना जैसी है -शांत, कोमल, और गहरी। वे न अपने खिलने का उत्सव मनाते हैं, न गिरने की पीड़ा में विलीन होते हैं। वे बस प्रवाह में रहते हैं, उस नदी की तरह जो कभी ठहरती नहीं, लेकिन अपने भीतर सैकड़ों स्मृतियों को संजोए रखती है। शाम की धूप जब सहजन के पेड़ों से छनकर गिरती है, तो फूलों के छोटे-छोटे चेहरे चमकने लगते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बस प्रकृति का एक कोमल संकेत है कि सौंदर्य उन्हीं चीज़ों में बसता है, जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। कभी-कभी, मैं सहजन के फूलों को देखता हूं और सोचता हूं - क्या हम भी ऐसे ही नहीं हैं? अपनी शाखाओं पर किसी अदृश्य वचन में बंधे हुए, एक दिन मिट्टी में लौट जाने के लिए? और अगर लौटना ही है तो क्यों न इन फूलों की तरह उतरें -सुगंध से भरे हुए, हल्के, और स्मृतियों में बसे रहने वाले?

कृषि क्षेत्र में दुनिया मे सबसे तेज वृद्धि भारत में दर्ज

-कांतिलाल मांडोत-

बीते एक दशक में भारतीय कृषि जिस मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है, वह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि गांव खेत और किसान की रोजमर्रा की जद्दोजहद का आईना भी है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल हो चुका है। वर्ष 2015 के मुकाबले 2024 तक किसानों की औसत आय में 126 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और सालाना वृद्धि दर दस प्रतिशत से अधिक रही है। यह दावा ऐसे समय में सामने आया है जब देश 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना देख रहा है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। ऐसे में कृषि क्षेत्र की यह तस्वीर उम्मीद भी जगाती है और कई सवाल भी खड़े करती है।

रिपोर्ट बताती है कि खेती आज भी देश के 46 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार दे रही है। यह अपने आप में बड़ा तथ्य है क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि विकास के साथ कृषि से लोगों का पलायन होगा। इसके उलट भारत में कृषि न सिर्फ रोजगार का बड़ा आधार बनी हुई है बल्कि इसमें महिलाओं की भागीदारी भी तेजी से बढ़ी है। 2017-18 के मुकाबले 2023-24 तक कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। यही स्थिति विनिर्माण क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। यह बदलाव सामाजिक संरचना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गहरे परिवर्तन का संकेत देता है।

कृषि विकास दर के आंकड़े भी इस दशक को ऐतिहासिक बनाते हैं। 2015-16 से 2024-25 के बीच कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.45 प्रतिशत रही है जो आजादी के बाद सबसे अधिक मानी जा रही है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह दर दुनिया की औसत कृषि विकास दर 2.88 प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। चीन अमेरिका ब्राजील इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे देशों की तुलना में भी भारत का प्रदर्शन बेहतर बताया गया है। इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय कृषि ने बीते दस वर्षों में दुनिया में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है।

इस वृद्धि के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। कृषि उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी एक बड़ा कारण है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में बीते वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां 2008 के आसपास धान का एमएसपी करीब 850 रुपए और गेहूं का लगभग 1000 रुपए था वहीं 2025-26 तक यह क्रमशः 2369 और 2425 रुपए के स्तर तक पहुंच चुका है। यानी करीब ढाई गुना वृद्धि। इसके साथ ही सरसों गेहूं और चना जैसी फसलों के दाम भी दो तीन हजार से बढ़कर पांच सात हजार रुपए तक पहुंचने की बात कही जा रही है। इससे किसानों को बेहतर भाव मिला है और आय में इजाफा हुआ है। तकनीक और सरकारी योजनाओं की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। ई नाम प्लेटफॉर्म से लेकर ड्रोन तकनीक सोलर पंप और प्रधानमंत्री कुसुम योजना जैसी पहलों ने खेती को पहले की तुलना में आसान और आधुनिक बनाया है। सिंचित क्षेत्र का विस्तार हुआ है कृषि यंत्रों पर अनुदान मिला है पाइपलाइन फव्वारा और खेत की तारबंदी तक के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है। इन सबका असर यह हुआ कि खेती की उत्पादकता बढ़ी और लागत के कुछ हिस्सों में राहत मिली।

खेती में विविधता भी आय बढ़ने का बड़ा आधार बनी है। परंपरागत अनाज के साथ फल सब्जी मसाले पशुपालन और मछली पालन जैसे क्षेत्रों को अपनाने से किसानों के पास आय के नए स्रोत खुले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पशुपालन के दम पर किसानों की आय 2016 से 2023 के बीच 107 प्रतिशत तक बढ़ी थी। यह दिखाता है कि जो किसान एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहे और बाजार की मांग के हिसाब से खुद को ढाला उन्होंने अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति हासिल की।

राजस्थान के कोटा जिले के लक्ष्मीपुरा गांव के किसान महावीर शर्मा की कहानी इसी बदलाव की मिसाल है। उन्होंने बिचौलियों को हटाकर किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने की पहल की। एक कंपनी बनाकर आसपास के किसानों को जोड़ा और पहले ही वर्ष में आठ करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन किया। इस मॉडल से किसानों को उचित मंडी भाव मिला और खरीद बिक्री में पारदर्शिता आई। यह दिखाता है कि संगठित प्रयास और बाजार की समझ से खेती भी लाभकारी व्यवसाय बन सकती है। इसी तरह कोटा के सांगोद क्षेत्र के किसान रविंद्र मेहता ने जैविक खेती को अपनाकर अपनी राह बनाई। पूरी तरह जैविक तरीके से गन्ने की खेती शुरू की और उससे गुड़ बनाकर पैकिंग के साथ बाजार में बेचना शुरू किया। इसके अलावा धान और खीरे जैसी फसलों से भी आय बढ़ाई। उनके खेत में यह दावा सच होता दिखता है कि किसानों की आय दोगुनी हो सकती है। आज उनके पास खेती से अर्जित संसाधनों के दम पर बेहतर जीवन सुविधाएं मौजूद हैं।

लेकिन इस चमकदार तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही सच है। श्रीगंगानगर जिले के चक महाराजका के किसान अमृतपाल सिंह संधू जैसे किसान मानते हैं कि कागजों में आय भले ही बढ़ी दिखाई दे लेकिन वास्तविक आय में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। वे सौ बीघा भूमि पर खेती करते हैं फिर भी खेती लाभ का सौदा नहीं रह गई है। बीज खाद कीटनाशक डीजल बिजली मजदूरी और मशीनों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो आय बढ़ी है वह बढ़ती लागत में ही समा जाती है। इस कारण किसानों को लगता है कि उनकी जेब में बचत पहले जैसी ही है। यही विरोधाभास इस पूरी बहस को जटिल बनाता है। एक तरफ औसत आय के आंकड़े हैं जो बड़ी वृद्धि दिखाते हैं तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत है जहां छोटे और मध्यम किसान आज भी जोखिम और अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। मौसम की मार बाजार के उतार चढ़ाव और प्राकृतिक आपदाएं खेती को अस्थिर बनाती हैं। बड़े किसानों की असंतुष्टि भी इसी संदर्भ में सामने आती है क्योंकि उनके निवेश और खर्च का स्तर अधिक होता है और लाभ अपेक्षाकृत कम महसूस होता है।

खान पान के आंकड़े भी ग्रामीण और शहरी भारत में बदलती आर्थिक स्थिति की झलक देते हैं। प्रति व्यक्ति औसत उपभोग में अनाज की मात्रा कुछ कम हुई है जबकि फल ड्राई फ्रूट्स मछली और मांस जैसे उत्पादों की खपत बढ़ी है। यह बदलाव आय में वृद्धि और खान पान की पसंद में बदलाव का संकेत देता है। साथ ही यह भी दिखाता है कि कृषि अब सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं है बल्कि पोषण और विविधता से जुड़ गई है।

नीति आयोग की रिपोर्ट देश के भविष्य के लक्ष्य से भी कृषि को जोड़ती है। 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति 12 लाख रुपए सालाना आय के लिए आठ प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर की जरूरत बताई गई है। इसमें कृषि की भूमिका सिर्फ सहायक नहीं बल्कि आधारभूत मानी जा रही है। जब तक गांव और किसान मजबूत नहीं होंगे तब तक समग्र विकास अधूरा रहेगा।

धन और ज्ञान मात्र संग्रह ही नहीं, सदुपयोग भी जरूरी है

धर्मकर्म

एक गांव में धर्मदास नामक एक व्यक्ति रहता था। बातें तो बड़ी ही अच्छी-अच्छी करता था पर था एकदम कंजूस। कंजूस भी ऐसा वैसा नहीं बिल्कुल मक्खीचूस। चाय की बात तो छोड़ो, वह किसी को पानी तक के लिये नहीं पूछता था। साधु-संतों और भिखारियों को देखकर तो उसके प्राण ही सूख जाते थे कि कहीं कोई कुछ मांग न बैठे। एक दिन उसके दरवाजे पर एक महात्मा आए और धर्मदास से सिर्फ एक रोटी मांगी। पहले तो धर्मदास ने महात्मा को कुछ भी देने से मना कर दिया लेकिन तब वह वहीं खड़ा रहा तो उसे आधी रोटी देने लगा। आधी रोटी देखकर महात्मा ने कहा कि अब तो मैं आधी रोटी नहीं, पेट भरकर खाना खाऊंगा। इस पर धर्मदास ने कहा कि अब वह कुछ नहीं देगा। महात्मा रातभर चुपचाप भूखा-प्यासा धर्मदास के दरवाजे पर खड़ा रहा। सुबह जब धर्मदास ने महात्मा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो सोचा कि अगर मैंने इसे भरपेट खाना नहीं खिलाया और यह भूख-प्यास से यहीं पर मर गया तो मेरी बदनामी होगी। बिना कारण साधु की हत्या का दोष लगेगा। धर्मदास ने महात्मा से कहा कि बाबा तुम भी क्या याद करोगे, आओ पेट भरकर खाना खा लो। महात्मा भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। धर्मदास की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि अब मुझे खाना नहीं खाना। मुझे तो एक कुआं खुदवा दो। लो अब कुआं कहां से बीच में आ गया धर्मदास ने साधु महाराज से कहा। धर्मदास ने कुंआ खुदवाने से साफ मना कर दिया। साधु महाराज अगले दिन फिर रातभर चुपचाप भूखा-प्यासा धर्मदास के दरवाजे पर खड़ा रहा। अगले दिन सुबह भी जब धर्मदास ने साधु महात्मा को भूखा-प्यासा अपने दरवाजे पर ही खड़ा पाया तो सोचा कि अगर मैंने कुआं नहीं खुदवाया तो यह महात्मा इस बार जरूर भूखा-प्यासा मर जाएगा और मेरी बदनामी होगी। धर्मदास ने काफी सोच-विचार किया और महात्मा से कहा कि साधु बाबा, मैं तुम्हारे लिये एक कुआं खुदवा देता हूं और इससे आगे अब कुछ मत बोलना। नहीं, एक नहीं अब तो दो कुएं खुदवाने पड़ेंगे, महात्मा की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थी। धर्मदास कंजूस जरूर था, बेवकूफ नहीं। उसने सोचा कि अगर मैंने दो कुएं खुदवाने से मना कर दिया तो यह चार कुएं खुदवाने की बात करने लगेगा इसलिए रामदयाल ने चुपचाप दो कुएं खुदवाने में ही अपनी भलाई समझीं।

आज का इतिहास

1503 - पुर्तगाली तथा उस्मानों (उस्मानी साम्राज्य (1299 - 1923) (या ऑटोमन साम्राज्य या तुर्क साम्राज्य) के बीच दीव की लड़ाई भारत के दीव (अब एक केन्द्र शासित प्रदेश) में हुई।

1760 - सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना ने उदगीर के युद्ध में निजाम को बुरी तरह हराया।

1815 - विश्व में पनीर उत्पादन का पहला कारखाना स्विटजरलैंड में खोला गया।

1916 - बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की शुरुआत।

1925 - भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा मुम्बई से कुर्ला के बीच शुरू।

1934 - पहली बार हवाई जहाजों से पार्सल भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। इसे शुरू करने वाले कंपनी को आज लुफ्थांसा के नाम से जाना जाता है।

1942 - जावा पर पहला जापानी हवाई हमला हुआ।

1945 - रूस द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने पर सहमत हुआ।

1954 - इलाहाबाद कुम्भ मेले में हुए हादसे में 500 से अधिक की मौत।

1969 - तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री सी.एन. अन्नादुरई का निधन।

1970 - भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की तलचर में आधारशिला रखी गई।

1972 - जापान के सप्पारो में एशिया में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया।

1988 - पहली परमाणु पनडुब्बी भारतीय सेना में शामिल।

1999 - भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में डेमोक्रेटिक जनता दल का पुनरुद्धार हुआ ।

1999 - विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की 29वीं वाषिक बैठक का दावोस (स्विटजरलैंड) में समापन।

2003 - भारत ने उजबेकिस्तान के साथ आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया।

2005 - भारतीय मूल के पहले सांसद दलीप सिंह सौंद को सम्मानित करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधी सभा में लाये गये विधेयक को आम राय से मंजूरी मिली।

सैनिटरी पैड: स्कूलों में गरिमा की परीक्षा

-डॉ. प्रियंका सौरभ-

सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूलों में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने और मासिक धर्म स्वच्छता को अनिवार्य करने संबंधी निर्देश केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं हैं, बल्कि यह भारतीय समाज की उस सामूहिक सोच को आईना दिखाते हैं, जिसमें आज भी मासिक धर्म को संकोच, चुप्पी और उपेक्षा के साथ देखा जाता है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि मासिक धर्म महज़ स्वास्थ्य या स्वच्छता का मुद्दा नहीं, बल्कि गरिमा, समानता और शिक्षा के अधिकार से जुड़ा एक गंभीर संवैधानिक प्रश्न है। भारत जैसे देश में, जहाँ संविधान समानता और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सुनिश्चित करता है, वहाँ लाखों छात्राओं का मासिक धर्म के दौरान असुरक्षित और अपमानजनक परिस्थितियों में पढ़ाई करने को मजबूर होना व्यवस्था की गहरी विफलता को उजागर करता है। अदालत का यह हस्तक्षेप इसी विफलता को दूर करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। यह याद दिलाता है कि अधिकार केवल काग़ज़ों में दर्ज घोषणाएँ नहीं होते, बल्कि उनका वास्तविक अर्थ तभी है, जब वे ज़मीनी हकीकत में दिखाई दें।

मासिक धर्म को लंबे समय तक केवल एक जैविक प्रक्रिया मानकर नज़रअंदाज़ किया जाता रहा है। परिणामस्वरूप यह विषय स्वास्थ्य मंत्रालय या स्कूल प्रबंधन की सीमित जिम्मेदारी बनकर रह गया। सच्चाई यह है कि मासिक धर्म सामाजिक, शैक्षिक और मानसिक स्तर पर गहरे प्रभाव डालता है। स्वच्छता सुविधाओं और सही जानकारी के अभाव में छात्राओं को न केवल संक्रमण और बीमारियों का खतरा रहता है, बल्कि शर्म और भय के कारण वे नियमित रूप से स्कूल आने से भी कतराने लगती हैं। कई मामलों में यह स्थिति स्थायी स्कूल ड्रॉपआउट का कारण बन जाती है। अनेक अध्ययन यह दर्शाते हैं कि मासिक धर्म के दौरान उचित प्रबंधन की कमी के कारण बड़ी संख्या में किशोरियाँ हर महीने कई दिनों तक स्कूल नहीं जातीं। यह अनुपस्थिति धीरे-धीरे सीखने की प्रक्रिया को कमजोर करती है और अंततः शिक्षा से पूरी तरह कट जाने का जोखिम बढ़ा देती है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या हम वास्तव में "सबके लिए शिक्षा" के लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं, या यह केवल नीतिगत दस्तावेज़ों तक सीमित नारा बनकर रह गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि मासिक धर्म स्वच्छता की अनदेखी सीधे तौर पर शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। जब स्कूलों में अलग और स्वच्छ शौचालय, साफ़ पानी, साबुन और सैनिटरी पैड जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं, तो छात्राओं के लिए नियमित रूप से विद्यालय जाना व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाता है। यह स्थिति लैंगिक असमानता को और गहरा करती है, क्योंकि जहाँ लड़कों की शिक्षा बिना किसी जैविक बाधा के चलती रहती है, वहीं लड़कियों को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण पीछे धकेल दिया जाता है।

यह असमानता संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 की भावना के विरुद्ध है, जो समानता और भेदभाव-रहित समाज की अवधारणा को आधार प्रदान करते हैं। केवल अवसर की समानता पर्याप्त नहीं होती, जब तक उस अवसर तक पहुँचने के साधन भी समान न हों। मासिक धर्म स्वच्छता की अनदेखी करके हम अनजाने में ही लड़कियों को उस बराबरी से वंचित कर देते हैं, जिसका वादा संविधान करता है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि मासिक धर्म से जुड़ी सुविधाओं का अभाव महिलाओं और किशोरियों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। जब किसी छात्रा को असुरक्षित और अवैज्ञानिक साधनों का उपयोग करने को मजबूर होना पड़े, तो यह केवल स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा पर सीधा आघात है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन को केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं करता, बल्कि आत्मसम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी सुनिश्चित करता है। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस धारणा को तोड़ता है कि सैनिटरी पैड या स्वच्छ शौचालय कोई "अतिरिक्त सुविधा" हैं। वास्तव में ये आवश्यक अधिकार हैं, जिनके बिना न तो स्वास्थ्य सुरक्षित रह सकता है और न ही शिक्षा का अधिकार सार्थक हो सकता है। इस दृष्टि से अदालत का यह आदेश एक सामाजिक चेतावनी के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

हालाँकि भारत में न्यायिक आदेशों की सबसे बड़ी चुनौती उनके प्रभावी क्रियान्वयन में दिखाई देती है। कई बार नीतियाँ और दिशा-निर्देश घोषणाओं और फाइलों तक सीमित रह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इस आशंका को ध्यान में रखते हुए कहा है कि यह निर्णय केवल अदालती आदेश या कानूनी पुस्तकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका वास्तविक असर स्कूलों और छात्राओं के जीवन में दिखाई देना चाहिए। सरकारी और निजी, शहरी और ग्रामीण-सभी स्कूलों में इन निर्देशों को समान रूप से लागू करना अनिवार्य है।

इस संदर्भ में निजी स्कूलों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अक्सर निजी शिक्षण संस्थान स्वयं को सरकारी योजनाओं और सामाजिक उत्तरदायित्व से अलग मान लेते हैं। अदालत का आदेश इस सोच को स्पष्ट रूप से खारिज करता है और बताता है कि बच्चों के अधिकार के मामले में सरकारी और निजी का भेद स्वीकार्य नहीं हो सकता। यदि निजी स्कूल उच्च शुल्क वसूल सकते हैं, तो वे छात्राओं की बुनियादी स्वच्छता और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि केवल आदेश और नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं। जब तक समाज की सोच में बदलाव नहीं आता, तब तक ऐसी पहल अधूरी ही रहेंगी। मासिक धर्म को लेकर फैली चुप्पी, अंधविश्वास और शर्म की भावना इस समस्या को और जटिल बनाती है। स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन केवल पैड वितरण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जागरूकता, संवाद और वैज्ञानिक जानकारी को भी शिक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बनाना चाहिए। लड़कों को भी इस चर्चा से अलग नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि संवेदनशील और समान समाज की नींव तभी पड़ती है, जब समझ साझा होती है।

केंद्र और राज्य सरकारों के लिए यह आदेश केवल अनुपालन की बाध्यता नहीं, बल्कि सुधार का अवसर है। पर्याप्त बजट आवंटन, प्रभावी निगरानी तंत्र और स्पष्ट जवाबदेही तय किए बिना यह पहल सफल नहीं हो सकती। अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा यह स्पष्ट संकेत देती है कि इस मुद्दे को अब और टाला नहीं जा सकता।

अंततः यह फैसला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी समाज की प्रगति का आकलन उसके सबसे कमजोर वर्ग के साथ किए गए व्यवहार से होता है। छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक सुविधाएँ देना कोई उपकार नहीं, बल्कि एक संवैधानिक दायित्व है। अब असली परीक्षा यह है कि यह निर्णय काग़ज़ों से निकलकर ज़मीन पर उतरता है या नहीं। यदि ऐसा होता है, तो यह न केवल स्कूलों की तस्वीर बदलेगा, बल्कि उस सोच को भी बदलने की दिशा में निर्णायक कदम होगा, जो अब तक मासिक धर्म को अधिकार नहीं, बल्कि बोझ समझती आई है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक आदित्य वशिष्ठ द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस, बी-42 सेक्टर-7 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से मुद्रित व बी-142/2, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 से प्रकाशित।
संपादकीय एवं संपर्क कार्यालय ए-152 सेक्टर-63, नोएडा-201301 **संपादक - आदित्य वशिष्ठ** कानूनी सलाहकार-पवित्र मोहन शर्मा आर.एन.आई. DELHIN/2012/42452
इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी होंगे। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। e-mail: Jbttimes2021@ gmail. Com

देश को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी : किरेन रिजिजू

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चीन सीमा विवाद को लेकर लोकसभा में दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन के नियमों का उल्लंघन किया और देश को कमजोर दिखाने की कोशिश की।

उन्होंने कहा कि राहुल को चीन सीमा के मुद्दे पर कांग्रेस की 'ऐतिहासिक गलतियों' के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। रिजिजू का यह बयान सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच हुए तीखे टकराव के बाद आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत से ही नियमों का पालन नहीं किया और एक ऐसी पुस्तक से उद्धरण देने लगे, जिसका न तो प्रकाशन हुआ है और न ही उसकी प्रामाणिकता स्पष्ट है। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित सरकार के सदस्यों ने आपत्ति जताई और लोकसभा अध्यक्ष ने नियम 349 के तहत स्पष्ट रूलिंग दी कि बिना सदन की अनुमति किसी अप्रकाशित पुस्तक या प्रकाशन का हवाला नहीं दिया जा सकता। इसके बावजूद राहुल ने अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी और बार-बार वही बात दोहराते रहे। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने लगभग आधे घंटे तक सदन का समय बर्बाद किया, नियमों का उल्लंघन किया और चीन सीमा के मुद्दे को उठाते रहे। क्या कांग्रेस 1959 और 1962 में चीन द्वारा कब्जाई गई जमीन वापस ला सकती है? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है और सशस्त्र बल पूरी तरह सक्षम हैं। रिजिजू ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संसद नियमों से चलती है।

कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुआ हो, संसद और उसके नियमों से ऊपर नहीं हो सकता। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी खुद को संसद से ऊपर समझते हैं और नियमों का पालन नहीं करते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा सदन में ताली बजाना भी दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य था। रिजिजू ने राहुल गांधी से अपील की कि वे स्वयं नियमों का पालन करें और अपने सांसदों को भी ऐसा करने की सलाह दें। उन्होंने दोहराया कि चीन सीमा के मुद्दे पर कांग्रेस को अपने 'पाप' स्वीकार कर देश से माफी मांगनी चाहिए।

रेल कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी उग्र आंदोलन को देगी जन्म : शिव गोपाल मिश्र

नई दिल्ली। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के आह्वान पर विभिन्न लंबित एवं न्यायसंगत मांगों के शीघ्र समाधान की मांग को लेकर सोमवार को पूरे भारतीय रेल में 'अखिल भारतीय मांग दिवस' मनाया गया। इस अवसर पर रेलवे की सभी शाखाओं में धरना-प्रदर्शन, रैलियां और सभाएं आयोजित की गईं।

रेल कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में रनिंग स्टाफ के लिए किलोमीटर भत्ता (केएमए) दरों में वृद्धि, लेवल-1 के 30 प्रतिशत पदों को लेवल-2 में उन्नयन, लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरना, बढ़ते रेल नेटवर्क को देखते हुए अतिरिक्त पदों का सृजन, लेवल-8 व 9 में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी भत्ता, जोखिम व कठिनाई भत्तों में वृद्धि, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करना, कर्मचारियों के माता-पिता को पास/पीटीओ व चिकित्सा सुविधा में शामिल करना, प्वाइंट्समैन श्रेणी के लिए चार-ग्रेड वेतन संरचना तथा ट्रैक मेंटेनरों की पेट्रोलिंग सीमा 12 किलोमीटर तय करने जैसी मांगें शामिल रहीं। दिल्ली में एआईआरएफ की सहयोगी इकाई नॉर्दर्न रेलवेमेंस यूनियन (एनआरएमयू) ने दोपहर बाद बड़ौदा हाउस स्थित उत्तर रेलवे मुख्यालय पर प्रदर्शन किया।

सभा को संबोधित करते हुए एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि यदि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों की मांगों का शीघ्र समाधान नहीं किया, तो संगठन को और तीव्र संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कठिन कार्य परिस्थितियों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों का तत्काल निपटारा किया जाना चाहिए। एनआरएमयू के केंद्रीय अध्यक्ष एसके त्यागी और मुख्यालय मंडल के सचिव संजीव सैनी ने भी संबोधित किया।

दिल्ली मंडल की ओर से गाजियाबाद, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (प्लेटफॉर्म संख्या-1) तथा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी विरोध प्रदर्शन किए गए, जिनमें मंडल सचिव अनूप शर्मा सहित अन्य नेताओं ने भाग लिया। एआईआरएफ के बैनर तले बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों ने भाग लेते हुए संघर्ष को और तेज करने की घोषणा की।

'मियां राजनीति' करने वालों से मैं नहीं डरता : हिमंत बिस्व सरमा

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने सोमवार को कहा कि वह 'मियां राजनीति'करने वाले लोगों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर उनके खिलाफ दिल्ली में कोई मामला दर्ज किया जाता है, तब भी वह भयभीत नहीं होंगे।

मुख्यमंत्री सोमवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 फरवरी को दिन के 11 बजे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तान लिंक से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि केवल गौरव गोगोई के पाकिस्तान लिंक ही नहीं, बल्कि एक बड़े नेटवर्क से जुड़े 'व्यापक षड्यंत्र' का भी खुलासा होगा। डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने आरोप लगाया कि 8 फरवरी के बाद उन्हें गालियां देने के लिए गौरव गोगोई दो अन्य नेताओं के पास जा रहे हैं, ताकि 'तीन गोगोई एक साथ' उनके खिलाफ खड़े हो सकें। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का समर्थन करने वाले नेताओं, विशेषकर अखिल गोगोई और लुरिनज्योति गोगोई पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि असम में अखिल गोगोई की सरकार 500 साल बाद भी नहीं आ सकती। डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार कहीं बनेगी तो वह असम में नहीं, बल्कि 'बांग्लादेश या पाकिस्तान में' बनेगी।

बंगाल के उद्योग जगत ने बजट को सराहा, बताया विकसित भारत का रोड मैप

कोलकाता। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर पश्चिम बंगाल के प्रमुख उद्योगपतियों, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्षों और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने इसे संतुलित और विकासोन्मुख बताया है। उद्योग जगत का मानना है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफेक्चरिंग, निवेश और रोजगार सृजन पर स्पष्ट फोकस दिखता है, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उद्योग जगत में इसे विकसित भारत का रोड मैप कहा है। हालांकि, एमएसएमई, पर्यटन और उपभोग बढ़ाने के लिए और ठोस नीतिगत समर्थन की जरूरत भी जताई गई है। चैंबर और औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों की प्रतिक्रियाभारत चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष नरेश पचीसिया ने कहा कि बजट में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत आधार तैयार करेगा। सोसाइटी ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स के अध्यक्ष संजय बुधिया ने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे, मैन्युफैक्चरिंग और निवेश को बढ़ावा देने वाले प्रावधान सकारात्मक हैं। इससे घरेलू उद्योग को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि, एमएसएमई सेक्टर के लिए और सीधी राहत की गुंजाइश थी। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने कहा कि बजट जेम और ज्वेलरी उद्योग के प्रति स्थिर और संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। कस्टम ड्यूटी और जीएसटी में कोई बढ़ोतरी नहीं होना, नीति स्थिरता, एमएसएमई और क्लस्टर सपोर्ट से इस सेक्टर को भरोसा मिला है।

सिंधिया ने भोपाल में स्वतंत्रता सेनानी उद्धवदास मेहता की स्मृति में जारी डाक टिकट का किया विमोचन

भोपाल। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार शाम भोपाल में स्वतंत्रता संग्राम के निडर सेनानी एवं आयुर्वेद भूषण स्वर्गीय पं. उद्धवदास मेहता 'भाईजी' की स्मृति में समर्पित विशेष स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 'भाईजी' का जीवन साहस, विचार और राष्ट्रभक्ति की वह प्रेरणा है, जिसने कलम को हथियार बनाकर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। यह डाक टिकट आने वाली पीढ़ियों तक उनके विचार पहुंचाने का संकल्प है। सिंधिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज अमृत काल से शताब्दी काल की ओर बढ़ रहा है। अमृत काल' में देश के उन गुमनाम नायकों को उनका उचित स्थान मिल रहा है, जिनकी भूमिका स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि 'विकसित भारत 2047 केवल एक नारा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकल्प है। इस संकल्प को साकार करने के लिए देश के हर

नागरिक को इस महायज्ञ में अपनी आहुति देनी होगी। भाईजी जैसे नायकों का सम्मान करके हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं और भविष्य के लिए प्रेरणा लेते हैं। सिंधिया ने कहा कि पं. उद्धवदास मेहता 'भाईजी' का जीवन साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रसेवा का जीवंत प्रतीक है।

उन्होंने 1934 में भोपाल के नवाबी शासन के दमनकारी रवैये के खिलाफ 'प्रजा पुकार' पत्रिका के माध्यम से जनता की आवाज बुलंद की। सत्ता के प्रलोभनों को ठुकराकर उन्होंने जेल की यातनाएं सहीं, लेकिन अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। वे भारतीय जनसंघ के प्रारंभिक स्तंभों में से एक थे, जिन्होंने राष्ट्रवाद की अलख जगाई। आज इस डाक टिकट के माध्यम से राष्ट्र उनकी सेवा और बलिदान को याद कर रहा है। सिंधिया ने भाईजी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का जिक्र करते हुए बताया कि 1934 में भोपाल रियासत में प्रजा मंडल आंदोलन के दौरान भाईजी ने 'प्रजा पुकार' नामक समाचार पत्र शुरू किया। इस पत्र के जरिए उन्होंने नवाबी शासन की मनमानी, करों की मनमानी वृद्धि और जनता के अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाई। इस पत्रकारिता और आंदोलन के कारण उन्हें कई बार जेल भेजा गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी उन्होंने जनसंघ के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत किया। भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी किए गए विशेष स्मारक डाक टिकट पर भाईजी की तस्वीर, 'प्रजा पुकार' का प्रतीक और उनके योगदान का संक्षिप्त उल्लेख है।

सिंधिया ने अंत में सभी से आह्वान किया कि विकसित भारत के इस महायज्ञ में हर नागरिक अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भाईजी जैसे महानायकों की स्मृति हमें यह याद दिलाती है कि राष्ट्रसेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस अवसर पर मध्य प्रांत संघचालक अशोक पांडे, भोपाल सांसद आलोक शर्मा, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

मप्र के शहडोल जिले में मिले दो बाघों के शव, करंट लगने से मौत की आशंका

शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में जयसिंहनगर वन परिक्षेत्र अंतर्गत मसिरा सर्किल में बीते 24 घंटों के दौरान दो बाघों (एक नर और एक मादा) के शव मिले हैं। जानकारी लगते ही वन विभाग ने क्षेत्र में घेराबंदी कर डॉग स्क्वाड के साथ जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के बाद वन विभाग की टीम ने आंशका जताई है कि करंट लगने से उनकी मौत हुई होगी।

वन विभाग के अनुसार, रविवार की रात जयसिंहनगर वन परिक्षेत्र अंतर्गत करपा बीच में सर्किल मसिरा के आरएफ 382 क्षेत्र के पास एक बाघ का शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और तत्काल जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच के दौरान सोमवार तड़के उसी क्षेत्र में एक बाघिन का शव भी बरामद हुआ। दोनों शव राजस्व क्षेत्र में एक-दूसरे के नजदीक पाए गए, जिससे यह पुष्टि हुई कि उनकी मौत एक ही घटना में हुई है। विभाग का कहना है कि प्रारंभिक जांच और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर दोनों बाघों की मौत बिजली के करंट से होने की आशंका है। जांच में यह सामने आया है कि एक किसान ने अपनी फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत में अवैध रूप से बिजली का तार बिछाया था। इसी तार

की चपेट में आने से दोनों बाघों की जान चली गई। क्षेत्र के डीएफओ तरुणा वर्मा ने बताया कि दो बाघों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किया जा सकेगा।

यह मामला वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत एक गंभीर अपराध है। नियमानुसार पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और जांच के सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया कि वन विभाग की डॉग स्क्वॉड टीम, फील्ड स्टाफ और अन्य विशेषज्ञ दल क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। संबंधित किसान की भूमिका की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से वन्यजीव प्रेमियों और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। वन विभाग का कहना है कि जल्द ही जांच पूरी कर मौत के कारणों का खुलासा किया जाएगा।

तकनीक और एआई आधारित सुधारों से भारत का भविष्य गढ़ेगा बजट: जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 केवल एक साल का बजट नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास का रोडमैप है। यह बजट तकनीक आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े संरचनात्मक सुधारों के जरिए भारत के भविष्य को आकार देगा। डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोमवार को मंत्रालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि बजट का पूरा प्रभाव समय के साथ समझ में आएगा, लेकिन इसकी सोच दूरगामी और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह बजट विकसित भारत की दिशा में अगले 25 वर्षों की मजबूत नींव रखता है। बजट का असली फायदा मध्यम वर्ग को स्वास्थ्य खर्च में लंबी अवधि की राहत के रूप में मिलेगा। उन्होंने कहा कि कैंसर, डायबिटीज और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में घरेलू स्तर पर सस्ती दवाएं, वैक्सीन और जांच सुविधाएं उपलब्ध होने से परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा।

उन्होंने बताया कि देश में 11-12 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं

और कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में बायोफार्मा, जीन-आधारित थेरेपी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीक में निवेश आम लोगों के लिए बड़ी राहत बनेगा। मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपये की 'बायोफार्मा शक्ति' योजना को बजट की अहम घोषणा बताया। भारत पहले ही दुनिया के प्रमुख बायो-मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल है और यह योजना जैविक दवाओं, बायोसिमिलर, वैक्सीन और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेगी। आने वाले समय में बायोटेक्नोलॉजी अगली औद्योगिक क्रांति बनेगी, जैसे पहले आईटी सेक्टर ने देश की अर्थव्यवस्था को बदल दिया था। डॉ. सिंह ने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र में एआई के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे किसानों को सटीक जानकारी, बेहतर फसल प्रबंधन और जोखिम से सुरक्षा मिलेगी। बजट का लाभ गरीब वर्ग और आकांक्षी मध्यम वर्ग दोनों तक पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि बजट में मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। उत्तर भारत में नए सुपर-स्पेशलिटी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जाएंगे और रांची व तेजपुर के संस्थानों को मजबूत किया जाएगा। साथ ही आयुर्वेद और फार्मा शिक्षा के नए संस्थान खोले जाएंगे, जिससे पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक शोध से जोड़ा जा सके। न्यूक्लियर, खनिज और हरित ऊर्जा पर जोर देते हुए डॉ. सिंह ने बताया कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए आयात शुल्क में छूट को 2035 तक बढ़ाया गया है, जिससे निवेश बढ़ेगा। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को भी बजट में खास महत्व दिया गया है।

बजट में विज्ञान अनुसंधान के लिए दो बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है जिसमें 30 मीटर का नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप और पैंगोंग झील के पास नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप शामिल है।

उन्होंने कहा कि बजट अनुसंधान, उत्पादन और उपयोग- तीनों को एक साथ जोड़ने वाला है। विज्ञान आधारित ये सुधार भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विकास समावेशी, टिकाऊ और नागरिक-केंद्रित रहे।

इंदौर में दूषित पानी से एक और मरीज की मौत

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से फैली बीमारी के कारण एक और मरीज की मौत हो गई। एक माह से भी अधिक समय से अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग महिला मरीज रविवार देर रात इलाज के दौरान तोड़ दिया। इसके बाद क्षेत्र में दूषित पानी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है।

जानकारी के अनुसार, भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैली बीमारी के बाद करीब एक माह पहले 65 वर्षीय अनिता कुशवाह की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनका 04 जनवरी से बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर थीं। रविवार की रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इस महिला के बेटे नीलेश ने बताया कि उनकी मां को पहले से कोई बीमारी नहीं थी। गत 28 दिसंबर को उल्टी-दस्त के कारण भाग्यश्री अस्पताल में भर्ती किया गया था। दो दिन बाद डिस्चार्ज होकर उन्हें घर पर लाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद फिर हालत बिगड़ी। इसके बाद

उन्हें 01 जनवरी को अरबिंदो अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें 04 जनवरी को बॉम्बे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ती गई। हालत गंभीर होने पर किडनी फेल हो गई, जिसके चलते लगातार हेमोडायलिसिस किया जा रहा था। फिर वेंटिलेटर पर भी लिया गया। इलाज के दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट भी आया।

इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. माधव हसानी ने बताया कि शासन की ओर से हायर सेंटर पर इलाज करवाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से मरीज को बचाया नहीं जा सका। महिला के पति मिल से रिटायर्ड हैं। परिवार में एक बेटा और दो बेटियां हैं।

अनिता कुशवाह का अंतिम संस्कार आज होगा। इंदौर में हुई इस मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 32 पहुंच गया है। हालांकि, अभी भी तीन मरीज गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से दो बॉम्बे हॉस्पिटल के आईसीयू में और एक अरविंदो हॉस्पिटल में इलाजरत है। इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब भी 24 घंटे संचालित है और दो एम्बुलेंस तैनात की गई हैं।

कश्मीर में रात का तापमान बढ़ा, श्रीनगर में 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज

श्रीनगर। पूरे कश्मीर में रात के तापमान में मामूली वृद्धि हुई श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो मौसमी औसत से तीन डिग्री अधिक है। कश्मीर में 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि 'चिल्लई कलां' की समाप्ति के बाद से श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे लेकिन लगातार बढ़ रहा है।

बारामूला जिले में गुलमर्ग का स्की रिसॉर्ट शून्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान के साथ जम्मू-कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया। दक्षिण कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अन्य स्थानों में, काजीगुंड का न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री, कोकेरनाग का न्यूनतम तापमान शून्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस नीचे और कुपवाड़ा का न्यूनतम तापमान शून्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। घाटी में 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि 'चिल्लई-कलां' की समाप्ति के बाद शनिवार को 20 दिवसीय 'चिल्लई खुर्द' (छोटी ठंड) शुरू हुई। चिल्लई खुर्द के बाद 10 दिवसीय 'चिल्लई बच्चा' मनाया जाएगा। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया है।

प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक बीज नीति तैयार करें : मुख्यमंत्री

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कृषि उत्पादन की वास्तविक शक्ति उच्च गुणवत्ता वाले, भरोसेमंद और प्रमाणित बीजों में निहित है। प्रदेश के लिए नई और आधुनिक 'बीज नीति' समय की मांग है। भूमि जोत लगातार घट रही है, ऐसे में ध्यान केवल रकबे पर नहीं, बल्कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने पर होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि उच्च उपज, रोग-प्रतिरोधी और जलवायु-सहिष्णु किस्मों के विकास को प्राथमिकता देते हुए ऐसी बीज नीति तैयार की जाए जो आने वाले वर्षों की कृषि चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करे। बीज नीति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने सोमवार को अगले पाँच वर्षों के लिए प्रदेश की बीज उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता और उपलब्धता को नए स्तर तक ले जाने के लिए ठोस रोडमैप तैयार करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीज उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण की पूरी प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग आवश्यक है, ताकि प्रमाणित बीज की कमी न हो और किसान सशक्त बन सकें। मुख्यमंत्री ने भरोसेमंद बीज आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर बीज की एंड-टू-एंड ट्रेसेबिलिटी को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिलावटी या अमानक बीजों के प्रति कोई भी ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी। किसानों तक पहुँचने वाला हर बीज पैकेट प्रमाणित, परीक्षणित और पूरी तरह मानक होना चाहिए। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर संस्थानों, उपकार तथा निजी बीज उद्योग को एक साझा मंच पर लाकर बीज अनुसंधान, नवाचार और किस्म-रिलीज प्रक्रिया को तेज़ करने की आवश्यकता बताई। फसल विविधीकरण को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने दलहन, तिलहन, मक्का, बाजरा, ज्वार और बागवानी फसलों के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता हेतु विशेष रणनीति तैयार करने को कहा। इसी क्रम में प्रदेश में अगले पांच वर्षों में कम से कम पाँच 'सीड पार्क' स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए। ये सीड पार्क उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता परीक्षण और भंडारण की सभी सुविधाओं से सुसज्जित एकीकृत परिसर होंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को बीज विकास कार्यक्रमों से सीधे जोड़ा जाए, ताकि अनुसंधान, प्रशिक्षण और खेत-स्तर पर तकनीक के प्रसार के बीच सुदृढ़ समन्वय स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नौ क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप एक-एक कृषि विज्ञान केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाए, जिससे क्षेत्र-विशेष की फसलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज और तकनीकी समाधान तैयार किए जा सकें। मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों को भी बीज विकास कार्यक्रमों से जोड़ने पर जोर दिया, ताकि स्थानीय अनुभव और आधुनिक तकनीक का प्रभावी समन्वय बन सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि अधिकाधिक ट्यूबवेलों को सौर ऊर्जीकरण से जोड़ा जाए, जिससे किसानों का सिंचाई खर्च कम हो और कृषि में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़े। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में स्थापित सोलर पैनल इकाइयों को प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि स्थानीय निर्माण को बढ़ावा मिलने से रोजगार, निवेश और कृषि अवसंरचना को मजबूती मिलेगी।

अन्त:फसली खेती को मिशन मोड में लागू करें, अन्नदाता की आय में होगा कई गुना इजाफा : मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को कृषि क्षेत्र में नई छलांग दिलाने का सबसे प्रभावी तरीका 'गन्ना के साथ तिलहनी एवं दलहनी अन्तःफसली खेती' को बड़े पैमाने पर लागू करना है। उन्होंने कहा कि यह मॉडल गन्ना किसानों की आय को केवल दोगुना नहीं, बल्कि 'बहु-गुणित' करने की क्षमता रखता है। मुख्यमंत्री सोमवार को इस विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी कहा कि गन्ने के साथ सरसों, मसूर, उर्द और मूंग जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की अंतःफसल किसानों को अतिरिक्त उत्पादन, कम लागत और पूरे वर्ष स्थिर आय उपलब्ध कराती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का क्षैतिज विस्तार अब संभव नहीं है, इसलिए ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के लक्ष्य के लिए उत्पादन बढ़ाने का एकमात्र रास्ता इकाई क्षेत्रफल से अधिक फसल उत्पादन है। उन्होंने कहा कि 'गन्ना आधारित अंतःफसली खेती उत्तर प्रदेश के कृषि भविष्य का नया मॉडल है। यह किसानों को अधिक उत्पादन, अधिक कमाई और जोखिम से सुरक्षा तीनों प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ने इस योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक मिशन मोड में लागू करने के निर्देश दिए। वर्तमान में प्रदेश में 29.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है, जिसमें 14.64 लाख हेक्टेयर नया बोया गया क्षेत्र और 14.86 लाख हेक्टेयर पेड़ी शामिल है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े क्षेत्र में तिलहन और दलहन की अंतःफसल जोड़ने से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और साथ ही प्रदेश एवं देश की तिलहन-दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को नई मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से क्रियान्वित करते हुए अंतःफसल का चयन वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक आधार पर किया जाए। उन्होंने आईआईएसआर की सिफारिशों के अनुसार रबी सीजन में सरसों और मसूर तथा जायद सीजन में उर्द और मूंग को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ने की पैदावार प्रभावित किए बिना अतिरिक्त फसल, अतिरिक्त लाभ और अतिरिक्त सुरक्षा, यही इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने इस योजना के लिए वर्षवार रोडमैप तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अतिरिक्त उत्पादन सीधे किसानों की आय में वृद्धि करेगा और राज्य के जीवीए में बड़ा योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सहायता और अनुदान का ढांचा स्पष्ट होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बड़े पैमाने पर अंतःफसलों को अपनाने से किसानों को तेज़ नकदी प्रवाह मिलेगा और एकल फसल जोखिम कम होगा, जिससे कृषि अधिक स्थिर और टिकाऊ बनेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल गन्ना क्षेत्र से जुड़े किसानों के लाभ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे प्रदेश के व्यापक कृषि परिदृश्य के परिवर्तन के रूप में लागू किया जाना चाहिए।

मेरा गांव, मेरा तीर्थ कार्यक्रम प्रेरणादायी: बृजेश पाठक

उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने श्री नागेश्वर धाम आश्रम का किया लोकार्पण

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सोमवार को मेरा गांव, मेरा तीर्थ कार्यक्रम के तहत तहसील बिन्दकी अंतर्गत विकास खंड खजुहा के ग्राम हिम्मतपुर स्थित श्री नागेश्वर धाम आश्रम का उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने शिलापट्ट का अनावरण कर लोकार्पण किया। इस मौके पर ग्राम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाओं को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने के बाद उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा गांव, मेरा तीर्थ कार्यक्रम प्रेरणादायी है। इससे प्रेरित होकर अपने गांव को समृद्धिशील बनाना है। हम सबको अपनी मातृभूमि से जुड़कर रहना चाहिए, क्योंकि हमारी मिट्टी हमें ऊर्जा देती है, जो लोग गांव से निकलकर अच्छे-अच्छे पदों पर कार्यरत है, उनको अपने जन्मभूमि से जुड़े रहना चाहिए। साथ ही गांव के विकास में अपना सकारात्मक सहयोग करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हम सब को अपनी संस्कृति और संस्कार को बढ़ाने की जरूरत है। जब गांव सशक्त होंगे तभी देश उन्नत करेगा, तभी प्रधानमंत्री के विजन वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से पात्रों को लाभांवित कराएं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि ग्राम में स्वास्थ्य शिविर लगाकर नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएं। इस मौके पर प्रभारी मंत्री अजीत पाल सिंह ने मेरा गांव, मेरा तीर्थ कार्यक्रम के तहत गांव को समृद्ध बनाने के लिए अपने-अपने विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर विधायक जहानाबाद राजेन्द्र सिंह पटेल, विधायक बिन्दकी जय कुमार सिंह जैकी, विधायक अयाह शाह विकास गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा, प्रमोद द्विवेदी नगर पालिका परिषद बिन्दकी अध्यक्ष राधा साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं संबंधित उपस्थित रहे।

विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर नदियों के संरक्षण के लिए चलाया जागरूकता अभियान

वाराणसी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर सोमवार को उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी (काशी) में श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर नदियों के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में नदियों से जुड़े जीव जंतुओं के चित्र, गंगा सहित माता की तरह हितकारिणी नदियों एवं जल स्रोतों की स्वच्छता का स्लोगन लिखी तख्तियां भी लहराई गई। इस दौरान द्वार पर मौजूद लोगों को आर्द्र भूमि के संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया।

अभियान के नेतृत्वकर्ता गंगा सेवक नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि नदियां और उनसे जुड़ी आर्द्रभूमियां हमारे साझा भविष्य के लिए जीवनदायिनी हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए हमें तत्काल साहसिक कदम उठाने होंगे। हमें जल प्रदूषण रोकना होगा, जैव विविधता को बचाना होगा और नदियों को सूखने से बचाने के लिए सामुदायिक भागीदारी बढ़ानी होगी। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि नदियों का स्वास्थ्य ही हमारे जल, पर्यावरण और आजीविका का आधार है और इनके बिना हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। नदियों और आर्द्रभूमियों को बचाना हम सभी के लिए ज़रूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनसे लाभान्वित हो सकें। जागरुकता अभियान में सतीश सोमानी, राहुल राय, अवंतिका शर्मा, शिवानी जायसवाल आदि ने भागीदारी की।

बजट से उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को मिलेगा नया आयाम: ए.के. शर्मा

▶▶ **नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बजट में किए गए जनकल्याणकारी प्रावधानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर जताया आभार**

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने केंद्रीय बजट, 2026 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे समावेशी विकास और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाली मजबूत आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के सभी वर्गों– गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, व्यापारी और शहरी-ग्रामीण आबादी-को साथ लेकर आगे बढ़ने वाला बजट है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और समेकित विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री शर्मा ने इस जनहितकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उनका विशेष आभार जताया। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के बाद मनगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से मिलकर उत्तर प्रदेश को विशेष प्राथमिकता देने के लिए उनका भी आभार जताया है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। बजट में किए गए प्रावधान सरकार की स्पष्ट सोच और दीर्घकालीन विकास रणनीति को दर्शाते हैं। बजट में सौर ऊर्जा से संबंधित प्रावधानों के संबंध में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सोलर ग्लास के मुख्य घटक सोडियम एंटीमोनाइट को कस्टम ड्यूटी से छूट दिए जाने से पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय तेजी आएगी। इससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ेगा। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने के प्रावधानों से शहरी निकाय आत्मनिर्भर बनेंगे। इससे उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी, विकास परियोजनाओं में निजी एवं संस्थागत निवेश बढ़ेगा और शहरों में आधारभूत सुविधाओं का व्यापक विस्तार संभव होगा। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि बजट में टियर-2 और टियर-3 श्रेणी के शहरों के लिए धन आवंटन में वृद्धि से उत्तर प्रदेश के लगभग 45 शहरों में आधारभूत संरचना के विकास को गति मिलेगी। इससे उभरते शहरों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के प्रयास और अधिक सशक्त होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट के प्रावधानों से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को पक्के आवास का सपना साकार करने का अवसर मिलेगा।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट, 2026 में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को विशेष महत्व दिया गया है। इससे औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और शहरी-ग्रामीण संतुलित विकास को नई गति मिलेगी, जिससे उत्तर प्रदेश को देश के विकास इंजन के रूप में और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। यह बजट समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकसित भारत की संकल्पना से जोड़ने वाला है और समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

बजट 2026-27 स्वास्थ्य व फार्मा क्षेत्र में नए युग की शुरुआत : अनुप्रिया पटेल

मीरजापुर। केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे ऐतिहासिक और दूरदर्शी बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट स्वास्थ्य एवं फार्मा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है।

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बजट में 10 हजार करोड़ रुपये की 'बायोफार्मा शक्ति' योजना, तीन नए नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च तथा उत्तर भारत में नए NIMHANS की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट 'विकसित भारत' और 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आने वाले पांच वर्षों में एक लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और डेढ़ लाख केयरगिवर्स तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं घर-घर तक पहुंच सकें।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बजट में किसान, युवा, महिलाएं और एमएसएमई सभी वर्गों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है। यह बजट समावेशी विकास को गति देगा और देश को एक स्वस्थ व सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।

एक व्यक्ति की धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या

कौशांबी। सैनी थाना क्षेत्र में घर के बाहर सो रहे एक व्यक्ति की अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। कौशांबी के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) राजेश कुमार सिंह ने बताया कि चाय की दुकान संचालित करने वाले कानेमई गांव निवासी गणेश प्रसाद लोधी (55) रविवार रात लोधी अपने घर के बाहर बरामदे में चारपाई पर सो रहे थे तभी देर रात अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर उनके सिर पर धारदार हथियार से वार किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम और पुलिस के अन्य अधिकारी भी पहुंच गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष समेत 23 लोगों पर एफआईआर

फर्रुखाबाद। मऊदरवाजा शाना पुलिस ने बिना अनुमति मशाल जुलूस निकालकर मुख्य बाजार में अफरा-तफरी फैलाने के मामले में युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष सहित 23 नामजद और 5 से 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि जुलूस के दौरान लाठी-डंडों में कपड़ा लपेटकर जआग जलाई गई, जिससे मानव जीवन व संपत्ति को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया।

अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने सोमवार को बताया कि थाना मऊ दरवाजा में तैनात उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर किया गया है। टाउन हॉल से तिकोना चौकी की ओर फर्रुखाबाद के मुख्य बाजार में यह जुलूस बिना किसी पूर्व अनुमति के निकाला गया। नारेबाजी और शोर-शराबे के बीच आग के साथ लापरवाहीपूर्ण कृत्य किए गये, जिससे बाजार में दहशत फैल गई। आग लगने के डर से दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं। भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

इस मामले में युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष अंकुर श्रीवास्तव, राजेंद्र सिंह चौहान, अंजुम उर्फ अंजु ,रोहन कश्यप, गोविंद बाथम , मुनब्बर, अनमोल, जय कश्यप, सचिन, अजीम, करीम, माजिद अली, कमल , आदित्य श्रीवास्तव उर्फ हनी, जतिन उर्फ जीतू श्रीवास्तव सहित कुल 23 नामजद और 5 से 7 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। मामले की विवेचना में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सिपाही का शव कमरे में फांसी पर लटका मिला, जांच में जुटी पुलिस

प्रयागराज। जिले के केन्द्रीय कारागार नैनी में तैनात सिपाही का शव कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नैनी कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चन्द्र यादव ने बताया कि मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र स्थित उम्मानपुर गांव निवासी पृथ्वी राज चौहान (26) केंद्रीय कारागार नैनी में सिपाही के पद पर तैनात था। कारागार के पास ही कमरा लेकर रहता था। सोमवार को उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर परिवार को खबर दी। प्रारंभिक जांच में प्रतीत हो रहा है कि सिपाही ने खुदकुशी की है इसके पीछे की वजह परिवार के आने के बाद ही पता चल सकेगी। मामले की छानबीन की जा रही है।

सीबीसीआईडी से रिटायर्ड दारोगा की हत्या

प्रयागराज। लालापुर थाना क्षेत्र में सीबीसीआईडी से रिटायर्ड दारोगा की सिर कूंचकर हत्या कर दी गई। सोमवार को सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने घटनास्थल की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चन्द्र यादव ने बताया कि लालापुर थाना क्षेत्र के चकशिवचेर गांव निवासी राम रतन मिश्रा (65) सीबीसीआईडी से दारोगा पद से रिटायर्ड थे। आज उनका शव लहूलुहान हालत में कमरे के अंदर जमीन पर पाया गया। उनके सिर और चहेरे पर वजनदार वस्तु से प्रहार किया गया हैं। घटना की जानकारी परिवार को उस वक्त हुई जब उन्हें जगाने के लिए कमरे में पहुंचे। कई बार आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो कमरे में पहुंचे परिजनों ने राम रतन का शव खून से लतपथ हालत में देखकर सहम गये। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल से साक्ष्य जुटाया। परिवार के लोग किसी भी रंजिश से इंकार कर रहे हैं। हत्या की वजह जानने के लिए तीन टीमें गठित की गई शीघ्र खुलासा किया जाएगा।

अटल आवासीय विद्यालय की परीक्षा के लिए आवेदन 15 फरवरी तक

प्रयागराज। मण्डलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने सोमवार को गांधी सभागार में अटल आवासीय विद्यालय, ग्राम बेलहट, तहसील कोरांव में वित्तीय वर्ष 2026-27 में कक्षा-6 व 9 में छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु होने वाली प्रवेश परीक्षा एवं शिक्षा की गुणवत्ता के सम्बंध में बैठक कर आवश्यक निर्देश दिये।

बैठक में उपश्रमायुक्त ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा-6 एवं 9 के छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु 08 मार्च को परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए फार्म भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रवेश हेतु छात्र-छात्राएं खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं श्रम विभाग कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते है। प्रवेश हेतु ऑनलाइन भी आवेदन किए जा सकते है। अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं कोविड काल में निराश्रित बच्चे, जिनका महिला एवं बाल विकास में पंजीयन हो अथवा मुख्यमंत्री बाल सेवायोजना के अर्न्तगत आते हों, पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए तहसील एवं जिला स्तर पर परीक्षा केन्द्र चयनित किए जाने हैं।

मण्डलायुक्त ने इस सम्बंध में जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रवेश परीक्षा सेंटर के लिए विद्यालयों का चयन किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा। मण्डलायुक्त ने कक्षा-6 एवं कक्षा-9 में छात्र-छात्राओं के प्रवेश के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराने के लिए कहा है, जिससे अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकें। मण्डलायुक्त ने अटल आवासीय विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए शिक्षा में और गुणवत्ता के लिए यदि किसी और संसाधन की आवश्यकता हो, तो उसको लिखित रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रधानाचार्य को कहा। बैठक में अटल आवासीय विद्यालय में गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान विषय के लिए समय-समय पर विषय विशेषज्ञ अध्यापकों की कक्षाएं आयोजित कराने को कहे जाने पर मण्डलायुक्त ने जिला विद्यालय निरीक्षक को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा।

उन्होंने कहा कि निरंतर रूप से बच्चों की मॉक परीक्षा ली जाये एवं पढ़ाई में कमजोर बच्चों को चिन्हित कर उनकी आवश्यकतानुसार विशेष कक्षाएं आयोजित की जाये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, उपश्रमायुक्त सुमित कुमार सहित समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे।

संभल जामा मस्जिद ने रमजान से पहले लाउडस्पीकर लगाने के लिए इजाजत मांगी

संभल। संभल की शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष ने आगामी रमजान महीने से पहले मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत के लिए सोमवार को जिलाधिकारी को पत्र लिखा। शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली ने पत्र में कहा कि रमजान के दौरान लाउडस्पीकर की जरूरत है ताकि मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले सभी नमाजियों को इमाम की आवाज साफ सुनाई दे। अली ने पत्रकारों से कहा कि 18 फरवरी से रमजान का महीना शुरू होने वाला है इसलिए मस्जिद में लाउडस्पीकर की जरूरत है ताकि इमाम द्वारा मस्जिद के अंदर दी जाने वाली नमाज और तकरीरें मस्जिद के अंदर दूर बैठे लोगों तक भी पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि यह मांग इमाम व नमाज़ियों के बीच किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए की गई है और रमजान की नमाज के दौरान इसकी जरूरत बताते हुए सरकारी नियमों के अनुसार इजाजत लेने का अनुरोध किया गया है। फरवरी 2025 में सार्वजनिक जगहों पर ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सरकार के आदेश पर हुई कार्रवाई के बीच मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए थे।

पश्चिम यूपी में एम्स के लिए चंदौसी सबसे उपयुक्त स्थान : गुलाब देवी

संभल। जनपद संभल के चंदौसी में माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री उत्तर प्रदेश (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित एम्स (AIIMS) को लेकर सोमवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सर्वहितकारी और सर्वकल्याणकारी बजट के लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को बधाई देती हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम यूपी में एम्स का बनना अब लगभग तय है।

राज्यमंत्री गुलाब देवी ने चन्दौसी को एम्स के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताते हुए कहा कि चन्दौसी पश्चिमी क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। यहां रेलवे जंक्शन की सुविधा है, गंगा एक्सप्रेसवे भी पास से गुजरता है और शिक्षा की बेहतर व्यवस्था पहले से मौजूद है। उन्होंने कहा कि यदि एम्स चन्दौसी में स्थापित होता है तो इससे आसपास के कई जनपदों को सीधा लाभ मिलेगा। मरीजों और उनके परिजनों को आवागमन में सुविधा होगी और यह स्थान सभी के लिए सहज रहेगा।

माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वह इस विषय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अनुरोध करेंगी और जनहित में चन्दौसी को एम्स के लिए चुने जाने की पहल करेंगी। बताते चलें कि चंदौसी विधानसभा सीट से गुलाब देवी भाजपा से विधायक हैं।

गुजरात जायंट्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की नजरें लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचने पर

वडोदरा। लगातार तीन बार उपविजेता रही दिल्ली कैपिटल्स की टीम महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के एलिमिनेटर मुकाबले में मंगलवार को यहां जब पहली बार प्लेऑफ में पहुंची गुजरात जायंट्स के खिलाफ उतरेगी तो उसकी कोशिश चौथी बार फाइनल में पहुंचने की होगी।

डब्ल्यूपीएल के छोटे से इतिहास में सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाली टीमों में शामिल दिल्ली कैपिटल्स ने एक बार फिर लीग चरण को सफलतापूर्वक पार करते हुए शीर्ष तीन में जगह बनाई। इसके साथ ही वह अब तक के सभी चार सत्रों में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली एकमात्र टीम बन गई है। मौजूदा सत्र में हालांकि दिल्ली का अभियान उतार-चढ़ाव भरा रहा है, जिसमें दबदबे वाले प्रदर्शन के साथ-साथ गिरावट भी देखने को मिली। टीम ने अब तक चार मैच जीते हैं और उसे इतने में हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली की गेंदबाजी की अगुवाई तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा ने की है। मौजूदा सत्र में 14 विकेट लेने वाली इस गेंदबाज ने आखिरी ओवरों में

काफी प्रभावित किया है। उन्हें बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरनी (14 विकेट) का अच्छा साथ मिला है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी हरफनमौला मारिजेन कैप (10 विकेट) ने गेंदबाजी में नियंत्रण और भरोसेमंद प्रदर्शन जारी रखा है। बल्लेबाजी में कैप की हमवतन लौरा वोल्वार्ट (241 रन) और लिजेल ली (240 रन) ने शीर्ष क्रम में मजबूती प्रदान की है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (208 रन) के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी हालांकि चिंता का विषय बनी हुई है। पिछले मैच में कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने दबाव की स्थिति में अपनी फॉर्म दोबारा हासिल की। वह इससे पहले पूरे सत्र में निरंतरता के लिए जूझती नजर आई थीं। गुजरात जायंट्स की टीम दूसरी ओर एलिमिनेटर में जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ उतरेंगी। उन्होंने लगातार तीन मैचों की हार के बाद शानदार वापसी करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई। टीम ने इस दौरान गत चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ 11 रन की अहम जीत भी हासिल की। यह दो बार की चैंपियन टीम के खिलाफ उनकी पहली जीत थी। टीम ने इस जीत से ही नॉकआउट में अपनी जगह पक्की की। लीग चरण के दोनों मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स को हराने से भी गुजरात को आत्मविश्वास मिलेगा। इन दोनों मैचों में न्यूजीलैंड की अनुभवी खिलाड़ी सोफी डिवाइन ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। डिवाइन इस टूर्नामेंट की सबसे शानदार खिलाड़ी रही हैं। वह आठ मैचों में 17 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। उन्होंने इसके साथ ही दो अर्धशतक की मदद से 237 रन भी बनाये हैं। डिवाइन का हरफनमौला प्रदर्शन गुजरात जायंट्स के लिए सबसे बड़ा हथियार रहा है और पहली बार फाइनल में पहुंचने की उनकी उम्मीदों में उनकी भूमिका एक बार फिर अहम होगी। गुजरात को जॉर्जिया वेयरहैम की लय में वापसी से भी मजबूती मिली है। उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 26 गेंदों में नाबाद 44 रन की आक्रामक पारी से टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

टीम को ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज बेथ मूनी और कप्तान एश्ले गार्डनर से भी अहम योगदान की उम्मीद होगी। एलिमिनेटर का विजेता पांच फरवरी को होने वाले फाइनल में पूर्व चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगा।

इस प्रकार है टीमें

- **दिल्ली कैपिटल्स:** जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), तानिया भाटिया, चिनेल हेनरी, लिजेल ली, निकी प्रसाद, शेफाली वर्मा, लौरा वोल्वार्ड्ट, लुसी हैमिल्टन, मारिजेन कैप, अलाना किंग, स्नेह राणा, प्रगति सिंह, मिन्नू मणि, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी, एड्डला स्त्रुजना।
- **गुजरात जायंट्स :** एशले गार्डनर (कप्तान), कनिका आहूजा, सोफी डिवाइन, भारती फुलमाली, किम गार्थ, काशवी गौतम, राजेश्वरी गायकवाड़, हैप्पी कुमारी, जिंतिमनी कलिता, तनुजा कंवर, बेथ मूनी (विकेटकीपर), रेणुका सिंह, अनुष्का शर्मा, शिवानी सिंह, आयुषी सोनी, जॉर्जिया वेयरहम, डैनी व्याट-हॉज।

मैच शाम 07:30 बजे शुरू होगा।

खेलमंत्री मांडविया ने 'माय भारत बजट क्वेस्ट 2026' लांच किया

नई दिल्ली। राष्ट्रीय आर्थिक चर्चा और विकास प्राथमिकताओं में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और आम बजट को लेकर उनकी समझ बेहतर बनाने के लिये खेल मंत्रालय ने सोमवार को राष्ट्रीय स्तर पर 'माय भारत बजट क्वेस्ट 2026' शुरू किया जिसमें विजेता को विकसित भारत के विजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद का मौका मिलेगा।

खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने पत्रकारों से कहा कि इस साल बजटीय भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद के दौरान युवाओं द्वारा दिये गए सुझावों की सराहना की और बताया कि कुछ सुझावों को 2026 . 27 के आम बजट में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 के जरिये हम देश के युवाओं की आवाज को मजबूती देने की कोशिश जारी रखेंगे। मांडविया ने बताया कि इस प्रतिस्पर्धा की शुरूआत तीन फरवरी से माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर के आनलाइन क्विज के जरिये होगी जो आम बजट पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें भागीदारी के लिये 17 फरवरी तक की समय सीमा है और युवा माय भारत पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें बजट पर आधारित 30 सवाल पूछे जायेंगे। उन्होंने आगे बताया कि प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश से विजेताओं को 17 फरवरी से तीन मार्च तक दूसरे दौर में भाग लेने का मौका मिलेगा जिसमें निबंध लेखन होगा। उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं को विकसित भारत के विजन के साथ बजट से जुड़े आठ विषय दिये जायेंगे जिनमें से चुनकर एक पर उन्हें निबंध लिखना होगा। खेलमंत्री ने बताया कि दस मार्च को प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर मेरिट सूची जारी की जायेगी। उन्होंने बताया कि विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विकसित भारत बजट के विजन पर संवाद का मौका मिलेगा।

हरमनप्रीत, मंधाना और दिव्या '2025 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन अवार्ड्स' के लिए नामांकित

नई दिल्ली। भारत की महिला विश्व कप 2025 की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर और उप-कप्तान स्मृति मंधाना तथा शतरंज की प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिव्या देशमुख '2025 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर' पुरस्कारों के लिए नामांकित हैं। पिस्टल निशानेबाजी में सनसनी मचाने वाली सुरुचि सिंह और ट्रैक एवं फील्ड एथलीट ज्योति याराजी इस प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार के लिए नामांकित अन्य दो खिलाड़ी हैं।

बीबीसी न्यूज की अंतरिम वैश्विक निदेशक फियोना क्रैक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि 'इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर' पुरस्कार पूरे भारत में महिलाओं की खेल प्रतिभाओं के एक

वर्ष का प्रतीक है और बीबीसी विश्व सेवा अन्य किसी भी मीडिया प्रदाता की तुलना में इन प्रयासों को प्रदर्शित करने और उनका जश्न मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि हम इन महिलाओं को भारत और दुनिया भर के दर्शकों के सामने अपनी मेहनत से हासिल की गई उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करके रोमांचित हैं।

शारदुल ठाकुर, जायसवाल की रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के लिए मुंबई टीम में वापसी

मुंबई। कप्तान शारदुल ठाकुर और भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को छह फरवरी से कर्नाटक के खिलाफ होने वाले रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के लिए सोमवार को मुंबई की टीम में शामिल किया गया। मुंबई की टीम चार जीत और तीन ड्रॉ से एलीट ग्रुप डी में शीर्ष पर रही जबकि कर्नाटक ने ग्रुप ए के अपने अंतिम लीग मैच में पंजाब पर रोमांचक जीत की बदौलत अंतिम आठ में जगह बनाई। मुंबई और कर्नाटक के बीच क्वार्टर फाइनल छह से 10 फरवरी तक यहां एमसीए-बीकेसी मैदान पर खेला जाएगा क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम सात फरवरी से शुरू हो रहे टी20 विश्व कप के मुकाबलों की मेजबानी करेगा। मौजूदा सत्र में जायसवाल दूसरी बार मुंबई के लिए खेलते हुए नजर आएंगे।

तिलक वर्मा और मयंक यादव टी20 अभ्यास मुकाबलों के लिए भारत ए टीम में

मुंबई। आक्रामक बल्लेबाज तिलक वर्मा को सोमवार को टी20 विश्व कप के अभ्यास मुकाबलों के लिए भारत ए टीम में शामिल किया गया जबकि लंबे समय तक चोट के कारण बाहर रहने के बाद तेज गेंदबाज मयंक यादव की भी टीम में वापसी हुई।

तिलक को ग्रोइन की चोट से पूरी तरह उबरने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) से खेलने की स्वीकृति मिल गई है। वह सीनियर राष्ट्रीय टीम में फिर से शामिल होने से पहले दो अभ्यास मैच में से एक में खेलेंगे। यह बाएं हाथ का बल्लेबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में हुई टी20 श्रृंखला में नहीं खेल पाया था जिसमें श्रेयस अय्यर को उनकी जगह

मौका दिया गया था। बीसीसीआई ने टीम की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ''तिलक वर्मा सीनियर टीम में शामिल होने से पहले एक अभ्यास मैच खेलेंगे।'' भारत ए की टीम सोमवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में अमेरिका से भिड़ेगी जबकि शुक्रवार को बेंगलुरु के सीओई में नामीबिया का सामना करेगी। आयुष बडोनी 15 सदस्यीय भारत ए टीम की कप्तानी करेंगे जिसमें नमन धीर, विपराज निगम और रियान पराग भी शामिल हैं।

मयंक स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण एक साल से अधिक समय से टीम से बाहर थे। गत चैंपियन भारत सात फरवरी को टी20 विश्व कप के पहले दिन अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा।

भारत ए टीम

आयुष बडोनी (कप्तान), नमन धीर, आशुतोष शर्मा, प्रियांश आर्य, एन जगदीशन, तिलक वर्मा, रियान पराग, मानव सुथार, अशोक शर्मा, उर्विल पटेल, गुरजपनीत सिंह, विपराज निगम, रवि बिश्नोई, खलील अहमद, मयंक यादव।

अनाहत ने वॉशिंगटन में पहला पीएसए कांस्य स्तर का खिताब जीता

नई दिल्ली। भारतीय युवा स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने शीर्ष वरीयता प्राप्त और दुनिया की 10वें नंबर की खिलाड़ी इंग्लैंड की जॉर्जिना केनेडी को 12.10, 11.5, 11. 7 से हराकर वॉशिंगटन में पीएसए कांस्य स्तर का खिताब जीता। विश्व रैंकिंग में 31वें स्थान पर काबिज 15 वर्ष की अनाहत ने स्क्वाश आन फायर ओपन जीता जो उनके कैरियर का 15वां खिताब है। जीत के बाद उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। मैं इन टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन करके अपनी रैंकिंग बेहतर करना चाहती थी। मुझे खुशी है कि ऐसा कर सकी।

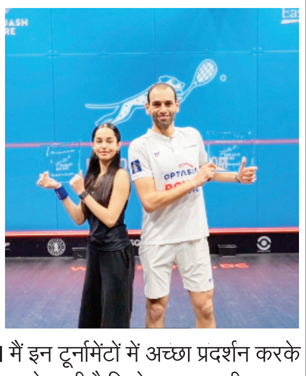

कारोबार

संक्षिप्त खबरें

एयरबस को भारतीय संचालक से तीन हेलीकॉप्टर का मिला ठेका

नई दिल्ली। एयरबस को एक भारतीय संचालक से तीन हेलीकॉप्टर का ठेका मिला है। एयरबस ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि एयरबस कॉरपोरेट हेलीकॉप्टर्स को दिए गए ठेके में दो एसीएच160 और एक एच175 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार '' यह संचालक पहले से एसीएच160 का ग्राहक है और भारत का पहला एच175 ग्राहक बनेगा।'' संचालक का नाम और सौदे से जुड़े वित्तीय विवरण कंपनी ने हालांकि साझा नहीं किए। कंपनी के अनुसार, एच175 हेलीकॉप्टर 16 सीट वाला होगा और इसकी आपूर्ति इसी साल की जाएगी। वहीं दो एसीएच160 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति 2027 में की जाएगी।

वित्त वर्ष 2026-27 का बजट वैश्विक स्थिरता को लेकर प्रतिबद्धता दर्शाता है : फिच

नई दिल्ली। भारत का बजट सरकारी कर्ज में क्रमिक कमी के जरिये व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसे वृद्धि संभावनाओं को मजबूत करने के लिए मजबूत पूंजीगत व्यय कार्यक्रम के साथ संतुलित किया गया है। फिच रेटिंग्स ने सोमवार को यह बात कही। बजट में हालांकि किसी बड़ पैमाने के सुधार की विशेष घोषणा नहीं की गई लेकिन फिच का मानना है कि उसे आगे और सुधारों की उम्मीद है खासकर विनियमन में ढील देने के एजेंडे पर। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मजबूत जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि भारत के कई संप्रभु ऋण मानकों में सकारात्मक गति ला रही है और यदि यह बनी रहती है, तो शेष राजकोषीय चुनौतियों के बावजूद समय के साथ देश की ऋण खाके में सुधार हो सकता है।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की जनवरी में कुल बिक्री 15 % बढ़कर 33,880 इकाई

नई दिल्ली। वाहन विनिर्माता कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की जनवरी में कुल बिक्री 15 प्रतिशत बढ़कर 33,880 इकाई हो गई। जनवरी 2025 में यह 29,371 इकाई रही थी। मोटर वाहन कंपनी ने बयान में कहा कि घरेलू बिक्री जनवरी 2025 की 26,178 इकाई के मुकाबले 17 प्रतिशत बढ़कर पिछले महीने 30,630 इकाई हो गई। वहीं निर्यात भी दो प्रतिशत बढ़कर 3,250 इकाई रहा जो एक साल पहले इसी महीने 3,193 इकाई रहा था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) के कार्यकारी उपाध्यक्ष (सेल्स-सर्विस-यूज्ड कार बिजनेस) सबरी मनोहर ने कहा, '' वर्ष 2026 की शुरुआत सकारात्मक और उत्साहजनक रही है।

देश के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधि में जनवरी में मामूली सुधार हुआ: PMI

नई दिल्ली। देश की विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में जनवरी में मामूली सुधार देखने को मिला। हालांकि नए ऑर्डर में तेजी से वृद्धि के बावजूद कारोबारी विश्वास साढ़े तीन साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। सोमवार को जारी मासिक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) दिसंबर के दो साल के निचले स्तर 55 से बढ़कर जनवरी में 55.4 रहा। खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) की भाषा में 50 से ऊपर का अंक विस्तार जबकि 50 से नीचे का अंक संकुचन दर्शाता है। एचएसबीसी की मुख्य अर्थशास्त्री (भारत) प्रांजुल भंडारी ने कहा, '' भारतीय विनिर्माण कंपनियों में जनवरी में सुधार देखा गया, जिसका कारण नए ऑर्डर, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि रही। कच्चे माल की लागत में मध्यम वृद्धि हुई जबकि 'फैक्ट्री-गेट' कीमतों में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी पड़ी जिससे विनिर्माताओं के मुनाफे पर हल्का दबाव पड़ा। '' 'फैक्ट्री-गेट' कीमत का मतलब वह कीमत

है जिस पर कोई उत्पाद उसके विनिर्माता के कारखाने या गोदाम से निकलता है। सर्वेक्षण में शामिल प्रतिभागियों ने कहा कि मांग में मजबूती, नए कारोबार में वृद्धि और प्रौद्योगिकी में निवेश ने उत्पादन को समर्थन दिया। कुल बिक्री को मुख्य रूप से घरेलू बाजार से गति मिली। हालांकि, निर्यात के नए ऑर्डर में भी वृद्धि हुई लेकिन उसकी रफ्तार अपेक्षाकृत कमजोर रही। जिन कंपनियों के निर्यात ऑर्डर बढ़े, उन्होंने एशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप और पश्चिम एशिया से अधिक मांग का हवाला दिया। रोजगार के मोर्चे पर, वस्तु उत्पादक कंपनियों ने अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति जारी रखी। हालांकि, रोजगार सृजन की गति 'मामूली' रही जो पिछले तीन महीनों में सबसे तेज रही। इस बीच, जनवरी में कारोबारी भरोसा साढ़े तीन साल के निचले स्तर पर आ गया। केवल 15 प्रतिशत कंपनियों ने आने वाले एक साल में उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई जबकि 83 प्रतिशत ने उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होने का अनुमान लगाया। भंडारी ने कहा, '' नए ऑर्डर में तेज वृद्धि के बावजूद कारोबारी विश्वास कमजोर बना हुआ है और भविष्य के उत्पादन को लेकर उम्मीदें जुलाई 2022 के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं।'' कीमतों के मोर्चे पर, सर्वेक्षण में कहा गया कि कच्चे माल की कीमतें चार महीनों के उच्चतम स्तर तक बढ़ीं लेकिन 'आउटपुट' (तैयार माल की) कीमतों में मुद्रास्फीति घटकर 22 महीने के निचले स्तर पर आ गई। एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण पीएमआई को एसएंडपी ग्लोबल ने करीब 400 कंपनियों के एक समूह में क्रय प्रबंधकों को भेजे गए सवालों के जवाबों के आधार पर तैयार किया है।

सात-आठ % की वृद्धि दर को कायम रखना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता: सीतारमण

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सात से आठ प्रतिशत की वृद्धि दर को कायम रखना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है, क्योंकि इससे सभी नागरिकों को फायदा होता है और रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होते हैं। रविवार को आम बजट 2026-27 पेश करने के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों के कॉलेज से आए विद्यार्थियों के साथ संवाद में सीतारमण ने कहा कि अगर आर्थिक वृद्धि की रफ्तार अच्छी होगी, तो इसका फायदा सभी नागरिकों तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा, ''और इसीलिए आर्थिक वृद्धि हमारी पहली प्राथमिकता है। हमें इसे उस स्तर पर बनाए रखना है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहने के लिए हमें सात प्रतिशत, आठ प्रतिशत वृद्धि के स्तर पर रहने की जरूरत है। इसलिए मैं जो कुछ भी करूंगी, वह इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए होगा।'' वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक वृद्धि से नौकरियां पैदा होती हैं, ज्यादा लोग श्रमबल से जुड़ते हैं और उत्पादकता बढ़ती है। सीतारमण ने आगे कहा कि नियोक्ता महिलाओं की दक्षता और सटीकता से काम करने की प्रतिभा के कारण श्रमबल में उनके योगदान को तेजी से पहचान रहे हैं। अर्द्धकुशल भूमिकाओं में महिलाओं की बढ़ती संख्या से इसका पता चलता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि निदेशक मंडल में महिलाओं के सीमित प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता बनी हुई है, और ज्यादा महिलाओं को नेतृत्व के पदों पर आगे आने की जरूरत है ताकि फैसले लेने में उनकी भूमिका हो और वे दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकें। उन्होंने कहा कि प्रगति हुई है, लेकिन अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने छात्र-छात्राओं को बताया कि पिछले बजट के बाद से, सरकार ने 'ऑरेंज' इकॉनमी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स क्षेत्र) के लिए लगातार नीतियां, वित्तपोषण और समर्थन सुनिश्चित किया है। उन्होंने कह कि आज का टेलीविज़न मीडिया भी ऐसी रचनात्मक सामग्री पर निर्भर करता है। यह कई अवसरों वाला एक शानदार क्षेत्र है। उन्होंने कहा, ''रचनात्मकता को हर दिन चुनौती मिलती है, और अगर आपमें काबिलियत है, तो यह निश्चित रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आगे बढ़ना चाहिए।'' वित्त मंत्री ने विद्यार्थियों को बजट तैयार करने में शामिल कदमों के बारे में भी बताया।

अशोक लेलैंड की जनवरी में कुल बिक्री 27 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली। वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड की कुल बिक्री जनवरी में 27 प्रतिशत बढ़कर 21,920 इकाई पर पहुंच गई। पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने 17,213 वाहन बेचे थे। अशोक लेलैंड ने मंगलवार को बयान में कहा कि उसकी घरेलू बिक्री 31 प्रतिशत बढ़कर 20,079 इकाई रही, जबकि जनवरी, 2025 में यह 15,327 इकाई थी। कंपनी ने बताया कि घरेलू बाजार में मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 12,833 इकाई रही, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 9,864 इकाई थी। कंपनी ने कहा कि पिछले महीने घरेलू बाजार में हल्के वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 7,246 इकाई रही।

जिंस की लागत में वृद्धि से कीमतों में बढ़ोतरी पर विचार किया जाएगा: मारुति सुजुकी

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) पार्थो बनर्जी ने सोमवार को कहा कि कंपनी बढ़ती जिंस लागत के मद्देनजर अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी पर विचार करेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती के बाद बाजार में मांग मजबूत बनी हुई है। बनर्जी ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उत्पादन संबंधी बाधाओं के कारण कंपनी के पास फिलहाल 1.75 लाख वाहनों के लंबित ऑर्डर हैं, जबकि केवल जनवरी में ही 2.78 लाख बुकिंग मिली है। उन्होंने कहा, ''जिंस के मोर्चे पर कीमतें बढ़ रही हैं। कीमती धातुओं में वृद्धि काफी ज्यादा है। भू-राजनीतिक हालात को देखते हुए हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले समय में कीमतों की समीक्षा जरूर करेंगे।''

कच्चे माल की लागत बढ़ने से निकट भविष्य में कीमतें बढ़ाने की संभावना से जुड़े सवाल पर उन्होंने यह बात कही। बनर्जी ने कहा, ''एक बाजार अग्रणी के तौर पर हमारा प्रयास हमेशा ग्राहकों पर लागत बढ़ोतरी का बोझ कम से कम रखने का रह+ा है। हमारी आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादन दल इस बात पर गौर कर रहे हैं कि जिंस की वजह से बढ़ी लागत को हम कितनी हद तक खुद वहन कर सकते हैं।'' उन्होंने हालांकि कहा, ''एक सीमा के बाद अगर हम लागत बढ़ोतरी को समायोजित नहीं कर पाए, तो हमें इसका बोझ ग्राहकों पर डालना पड़ेगा।'' संभावित कीमत बढ़ोतरी के लिए कोई समय-सीमा बताए बिना बनर्जी ने कहा कि कंपनी ने जनवरी में उन ग्राहकों के लिए 'प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम' (कीमत सुरक्षाा योजना) शुरू की है, जिनकी बुकिंग के बावजूद आपूर्ति नहीं हो पाई।

सितंबर 2025 में जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद कंपनी ने एस-प्रेसो की कीमत में 1,29,600 रुपये तक, ऑल्टो के.10 में 1,07,600 रुपये तक, सेलेरियो में 94,100 रुपये और वैगन-आर में 79,600 रुपये तक की कटौती की थी। यात्री वाहन उद्योग के परिदृश्य पर पूछे गए सवाल पर बनर्जी ने कहा, '' मोटर वाहन उद्योग फिर से छह से सात प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर लौट सकता है। हालांकि, मौजूदा समय में जिंस कीमतें काफी तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसे में भू-राजनीतिक हालात को देखते हुए इंतजार करना होगा, तभी बेहतर अनुमान लगाया जा सकेगा।'' उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 सुधारों से मोटर वाहन उद्योग को जो बढ़ावा मिला है और केंद्रीय बजट 2026-27 में बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय बढ़ाने की घोषणा ''मोटर वाहन उद्योग के लिए काफी सहायक साबित होगी।'' जनवरी की बिक्री पर बनर्जी ने कहा कि कंपनी ने अब तक की सबसे अधिक मासिक कुल बिक्री 2,36,963 इकाई दर्ज की है। उन्होंने कहा, ''हमें 2.78 लाख से अधिक बुकिंग मिली जो सालाना आधार पर 25 प्रतिशत की वृद्धि है। हमें रोजाना करीब 9,000 से 10,000 बुकिंग मिल रही है।'' उन्होंने बताया कि जनवरी में कंपनी का निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हुए 51,020 इकाई रहा। बनर्जी ने कहा कि कंपनी की नई एसयूवी 'विक्टोरिस' ने पांच महीने में 50,000 इकाई की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है।

रणबीर कपूर की 'रामायण' पर अरुण गोविल का बड़ा बयान

प्रभास स्टारर 'आदिपुरुष' को लेकर हुए विवादों और दर्शकों की निराशा के बाद अब हर किसी की नजर रणबीर कपूर की मेगा बजट फिल्म 'रामायण' पर टिकी है। करीब 4,000 करोड़ के बजट में बन रही इस फिल्म को लेकर फैंस के मन में उत्सुकता के साथ संशय भी है। ऐसे में टीवी के प्रतिष्ठित 'राम' अरुण गोविल ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी है। खास बात यह है कि वह इस फिल्म में राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे हैं। अरुण गोविल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसी भी कलाकार के लिए भगवान का किरदार निभाना सिर्फ अभिनय नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उनके मुताबिक, ₹भगवान की भूमिका निभाने के लिए इंसान की आत्मा का साफ और अच्छा होना बहुत जरूरी है। साथ ही वह एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए।₹ उन्होंने निर्देशक नितेश तिवारी की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी टीम ने इस फिल्म पर बेहद मेहनत की है। रणबीर कपूर को लेकर उन्होंने सकारात्मक राय देते हुए कहा कि वे न केवल शानदार अभिनेता हैं, बल्कि अच्छे इंसान भी हैं और भगवान राम के रूप में प्रभावशाली लग रहे हैं। अरुण गोविल ने साफ कहा कि रणबीर कपूर की 'रामायण' की तुलना 'आदिपुरुष' से करना गलत होगा। उनके अनुसार हर निर्देशक का विजन अलग होता है और किसी एक फिल्म की असफलता के आधार पर दूसरी फिल्म को पहले से जज करना सही नहीं। उन्होंने कहा कि 'आदिपुरुष' एक अलग तरह का प्रयास था, जबकि 'रामायण' एक नया और स्वतंत्र प्रोजेक्ट है, जिसे उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। अरुण गोविल ने यह भी माना कि जब एक मानक स्थापित हो जाता है तो तुलना होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा, भगवान की भूमिका निभाने के लिए लुक बहुत मायने रखता है। दर्शकों को स्क्रीन पर देखते ही महसूस होना चाहिए कि वे सच में भगवान को देख रहे हैं।₹ 68 वर्षीय अरुण गोविल ने बताया कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग काफी पहले पूरी कर ली थी। यह फिल्म नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियो द्वारा बनाई जा रही है, जिसमें यश की कंपनी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस भी सहयोग कर रही है। फिल्म आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक वीएफएक्स की मदद से दर्शकों को हजारों साल पुराने युग में ले जाने का प्रयास करेगी। भव्य पैमाने, दमदार स्टारकास्ट और मजबूत तकनीकी टीम के साथ 'रामायण' को भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है।

अरिजीत सिंह के सुरों से सजा 'इश्क का फीवर', 'ओ रोमियो' का नया गाना रिलीज

बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपने तीखे और रोमांटिक अंदाज के साथ लौटने के लिए तैयार हैं। उनकी आगामी फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी को वैलेंटाइन वीक के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म का निर्देशन मशहूर फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज ने किया है और इसे साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म में पहली बार शाहिद कपूर की जोड़ी अभिनेत्री तृप्ति डिमरी के साथ बनी है। फिल्म का नया गाना 'इश्क का फीवर' अब रिलीज कर दिया गया है, जिसमें शाहिद का स्टाइलिश और दीवाना-ए-इश्क अंदाज़ देखने को मिल रहा है। यह गाना टी-सीरीज़ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जारी हुआ है और रिलीज होते ही फैंस के बीच चर्चा में आ गया है। गाने में शाहिद और तृप्ति की फ्रेश केमिस्ट्री स्क्रीन पर खूब जच रही है। रोमांस के साथ हल्की जलन और जुनून का मिश्रण इस गाने को और दिलचस्प बना देता है। मशहूर गायक अरिजीत सिंह ने 'इश्क का फीवर' को अपनी आवाज दी है। गाने के बोल दिग्गज गीतकार गुलज़ार ने लिखे हैं, जबकि इसका संगीत विशाल भारद्वाज ने तैयार किया है। मेलोडी और इमोशन का संतुलन इस ट्रैक को खास बनाता है। बताया जा रहा है कि 'ओ रोमियो' की कहानी चर्चित किताब 'माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' से प्रेरित है। फिल्म में रोमांस, ड्रामा और अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि का अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा। शाहिद और तृप्ति के अलावा फिल्म में नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी, फरीदा जलाल जैसे दमदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं, विक्रांत मैसी भी विशेष उपस्थिति दिखेगी।

बॉक्स ऑफिस पर 'बॉर्डर-2' का जलवा, 300 करोड़ क्लब में शामिल

भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर लगातार दम दिखा रही है। 23 जनवरी को रिलीज हुई इस मल्टीस्टारर की रफ्तार 10 दिन बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही। वीकेंड पर फिल्म ने कमाई में जबरदस्त उछाल दर्ज किया है और कई नए रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। पहले हफ्ते में मजबूत पकड़ बनाने के बाद फिल्म ने दूसरे वीकेंड पर फिर से जोरदार वापसी की। रिपोर्ट्स के अनुसार, 10वें दिन यानी दूसरे रविवार को फिल्म ने 24.22 करोड़ की कमाई की, जबकि शनिवार (9वां दिन) का कलेक्शन 20.17 करोड़ रहा। इसके साथ ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 301.89 करोड़ तक पहुंच गया है। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी 'बॉर्डर 2' को दमदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। शुरुआती वीकडे में हल्की गिरावट के बाद फिल्म ने वीकेंड पर दोबारा जोर पकड़ा। वैश्विक स्तर पर फिल्म ने 10 दिनों में करीब 377 करोड़ की कमाई कर ली है। इस कमाई के साथ 'बॉर्डर 2' ने कई चर्चित फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। इनमें 'आदिपुरुष' (लगभग 355 करोड़), 'फाइटर' (लगभग 354 करोड़), और 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (लगभग 343 करोड़) शामिल हैं। इन आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि 'बॉर्डर 2' सिर्फ एक सफल सीक्वल नहीं, बल्कि मौजूदा दौर की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में अपनी जगह बना चुकी है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले दिनों में फिल्म कई और बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है।